



जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चुरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

Coming Home To The Bulbul, the Crow Pheasant, and...

Chital sometimes tend to get too nervous and will sound their high-pitched bark even at shadows. But Sambar will not call until they can see the tiger or leopard

Celebrating Positivity, One Smile at a Time

लोकसभाध्यक्ष दुविधापूर्ण विडंबना में फंसे

उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को तो पुस्तक के अंश उद्धृत करने दिए पर राहुल गांधी को पूर्व सेनाध्यक्ष नरवाणे की पुस्तक के अंश पढ़ने की इजाज़त नहीं दी

- रेणु मिश्रल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 4 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब नहीं दे सके क्योंकि लोकसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा किया। राहुल गांधी को लड़ाख में चीन के हमले पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब के बारे में बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद यह हंगामा हुआ।
ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री कल लोकसभा में भी भाषण नहीं देंगे और संभव है कि वह राज्यसभा में जवाब दें, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है।
हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकार आखिरी कोशिश कर रही है कि गतिरोध खत्म हो और विपक्ष से बातचीत शुरू हो सके। इसके लिए भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा जवाबलाल नेहरू के खिलाफ बोले गए सभी आपत्तिजनक शब्द हटाए जा सकते हैं। वह किताबों से उद्धरण दे

- लोकसभाध्यक्ष की इस “विवादपूर्ण” व्यवस्था के कारण, कांग्रेस ने भारी हंगामा किया और प्र.मंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर नहीं देने दिया।
- राहुल गांधी ने भाजपा सदस्यों की आपत्ति, कि पूर्व सेनाध्यक्ष नरवाणे की किताब अभी प्रकाशित हुई नहीं हुई उस अप्रकाशित पुस्तक के अंश कैसे लोकसभा में पढ़े जा सकते हैं, के जवाब में कहा, वे प्रकाशित पुस्तक की प्रति साथ लाए हैं, तथा उसकी प्रति प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे, जब प्र.मंत्री सदन में आएंगे।
- इस विवादित प्रकरण का अन्य पहलू यह भी है कि वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह व गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दावा किया था कि पूर्व सेनाध्यक्ष की पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, पर, राहुल गांधी ने कहा कि वे पुस्तक की प्रतिलिपि सदन में लाए हैं।
- तो क्या कांग्रेस, वरिष्ठ मंत्रीगणों के खिलाफ मिथ्यावचन का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का मामला बनाएगी।

रहे थे और स्पीकर ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की।
विपक्ष ने पूछा कि, क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के साथ व्यवहार के अलग-अलग मानदंड अपना रखे हैं।
इसी के विरोध में कांग्रेस सांसद स्पीकर के कक्ष में पहुंच गए और उनसे

कड़ा विरोध जताया। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी को पत्रिका के लेख से उद्धरण देने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, जबकि निशिकांत दुबे को ऐसा करने दिया गया।
इस मुद्दे पर स्पीकर मुश्किल स्थिति में नजर आ रहे हैं।
एक दिलचस्प घटनाक्रम में राहुल

गांधी संसद में जनरल नरवणे की किताब को एक प्रति लेकर आए। उन्होंने मीडिया को वह किताब दिखाई और कहा कि जब प्रधानमंत्री सदन में आएंगे तो वह उन्हें इसकी एक प्रति देंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आएंगे।
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल और मंत्री बिट्टू के बीच झड़प

- जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 फरवरी। आज सुबह संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई। दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदर्शन के दौरान गांधी ने पूर्व कांग्रेस नेता को "गद्दार दोस्त" कहा। इसके जवाब में बिट्टू ने गांधी को "देश का दुश्मन" बताया।
बिट्टू तीन बार सांसद रह चुके हैं और रेलवे राज्य मंत्री हैं। उन्होंने 2024

- राहुल गांधी जब कांग्रेस सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर धरना दे रहे थे, तो वहां से गुजर रहे मंत्री रवनीत बिट्टू, जो पहले कांग्रेस में थे, को उन्होंने "गद्दार दोस्त" कहा, बदले में बिट्टू ने उन्हें "देश के दुश्मन" करार दिया।

लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा जॉइन कर ली थी।
यह छोटी बहस उस समय हुई जब संसद के मकर द्वार के पास कांग्रेस सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। जब बिट्टू पास से गुजरे तो गांधी ने कहा, " देखो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को अपना “राजनीतिक मंच” बनाया

न्यायालय ममता जी की इस रणनीति का “बेबस” मूकदर्शक बनकर रह गया और ममता जी को निर्बाध रूप से पन्द्रह मिनट तक मुख्य चुनाव आयुक्त को भला-बुरा कहने का पूरा मौका मिला

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 फरवरी। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख, ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य जजों के सामने चल रही कानूनी सुनवाई को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय के खिलाफ एक राजनीतिक भाषण में बदल दिया और इसमें बड़ी जीत हासिल की।
ममता बनर्जी ने बेहतरीन तरीके से राजनीतिक चाल चली और कोर्ट की कार्यवाही को बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई में बदल दिया। बनर्जी ने राज्य में अपने समर्थकों से वादा किया था कि वह बंगाल में मतदाता सूची का संशोधन बिल्कुल नहीं होने देंगी।
अब जब मतदाता सूची का संशोधन (रोल रिविजन) लगभग पूरा

- इस दुःखद घटनाक्रम का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि पश्चिम बंगाल में फर्जी मतदाता की रणनीति को तृणमूल कांग्रेस ने एक कला का रूप दे दिया है, निरंतर सुधार-संवार कर।
- 56 लाख से भी ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए थे, गत सूची पर गहराई से काम करने से। इसके अलावा गत सूची में बहुत से नाम उन व्यक्तियों के हैं, जो मृत हो चुके हैं तथा नियमित रूप से बांग्लादेश से, सीमा पार से, गैर कानूनी घुसपैठिए आकर चुनावों में मतदान करते रहे हैं।
- एसआईआर (वोटर सूची का शुद्धिकरण) 4 नवंबर 2025 को आरंभ हुआ था। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में परिवर्तन की अंतिम तारीख 19 जनवरी थी और फाइनल सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होनी है।

हो चुका था और प्रक्रिया समाप्त होने वाली थी, तब ममता को लगा कि उन्हें बड़ा झटका लगा है। पिछली मतदाता

सूचियों से बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भूमिगत “चिकन नैक” रेल्वे ट्रैक बिछाने का काम शुरू

चिकन नैक एक संकड़ा भू भाग है, जो देश के नॉर्थ ईस्ट भाग को शेष भारत से जोड़ता है

- श्रीरंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 4 फरवरी 'चिकन नैक' की सुरक्षा से जुड़े 'शोध प्राथमिकता' वाले प्रोजेक्ट के तहत 40 किलोमीटर लंबे भूमिगत रेल कॉरिडोर के निर्माण का काम जल्द ही तेजी से शुरू किया जाएगा, यह दावा नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) के अधिकारियों ने किया है।
बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से घिरे तथा सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर-जिसे 'चिकन नैक' भी कहा जाता है-के माध्यम से ही पूर्वोत्तर राज्यों का शेष भारत से जमीनी संपर्क संभव है। भारत की सबसे कमजोर कड़ी कहे जाने वाले इस संकरे भू-भाग की चौड़ाई लगभग 20-22 किलोमीटर है और यह चीन की चुम्बी घाटी से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
हाल के महनों में बांग्लादेश के

- 20-22 किलोमीटर चौड़ा, यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे ही चिकन नैक कहते हैं, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और चीन की सीमा से मात्र 130 किलोमीटर दूर है।
- बांग्लादेश के चीन के करीब जाने व चीन की मदद से चिकन नैक हथियाने के दावों के मद्देनज़र भारतीय रेल्वे ने भूमिगत रेल्वे ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया है, क्योंकि किसी भी संकट की स्थिति में भी अंडरग्राउण्ड ट्रैक बाधित नहीं होगा।

चीन के करीब जाने के बाद 'चिकन नैक' को लेकर कूटनीतिक तनाव बढ़ा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूहों ने भारत के पूर्वोत्तर भाग को अलग-थलग करने के उद्देश्य से चिकन नैक को जाम करने की खुली अपील की है, साथ ही कुछ उग्रवादी संगठनों ने इस कॉरिडोर को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की अपनी परिकल्पना का हिस्सा बताया है।
इस खंड में भूमिगत रेल लाइन

बनाकर भारत संभावित सुरक्षा खतरों से निपटना और सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है। एनएफआर के महाप्रबंधक चेतन श्रीवास्तव ने कहा कि यह रेल खंड पश्चिम बंगाल में टिन माइल हाट से रंगापानी स्टेशन तक चलेगा।
2017 में चीन के साथ डोकलाम गतिरोध के दौरान सैन्य योजनाकारों ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बोत्सवाना से 8 चीते 28 को मध्यप्रदेश आर्येंगे

भोपाल, 04 फरवरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर असम से जंगली भैंसा मध्यप्रदेश लाने की प्रक्रिया सहित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की।

- असम से जंगली भैंसे भी मध्यप्रदेश लाने की तैयारी चल रही है।

उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 चीते मध्यप्रदेश लाए जाएंगे। चीतों के पुनर्स्थापन को लेकर केंद्रीय मंत्री यादव से आवश्यक व्यवस्थाओं एवं सहयोग पर भी विस्तार से चर्चा हुई है।

डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास, रिजर्व फॉरेस्ट के विस्तार और वन्य जीव संरक्षण की असीम संभावनाएं हैं। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल चुनावों पर देर रात भाजपा की बैठक मंगलवार देर रात केन्द्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के घर हुई इस मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन भी मौजूद थे

- बैठक का फोकस मुख्य रूप से एसआईआर के संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रणनीति का जवाब देने पर रहा, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी ने बेहद आक्रामक रुख अपना रखा है।
- मीटिंग में पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद शामिल हुए तथा पार्टी अध्यक्ष नबीन ने हरेक सांसद के साथ अलग-अलग मुलाकात कर फीडबैक लिया।
- सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में केन्द्रीय बजट को “यंग इंडिया” बजट के रूप में प्रचारित करें। इसके अलावा राज्य सरकार की विफलताओं पर आक्रामक रुख अपनाने और आंदोलन करने का निर्देश दिया गया, साथ ही कहा गया कि चुनाव होने तक आंदोलन जारी रहने चाहिए।

एसआईआर मुद्दे से निपटने की रणनीति पर था। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया।
बैठक का प्रमुख फोकस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा

करीब तीन घंटे चली इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने की। सभी सांसदों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर बजट 2026 के प्रमुख प्रावधानों को जनता के बीच स्पष्ट रूप से रखें। युवाओं तक पहुंच बनाने पर विशेष ज़ोर दिया गया

अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने की। सभी सांसदों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर बजट 2026 के प्रमुख प्रावधानों को जनता के बीच स्पष्ट रूप से रखें। युवाओं तक पहुंच बनाने पर विशेष ज़ोर दिया गया

और बजट 2026 को यंग इंडिया का बजट के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति बनाई गई है।
भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए एक बड़ा और दीर्घकालिक प्लान तैयार किया है। इसी योजना के तहत नितिन नबीन ने सांसदों के साथ एक-एक कर व्यक्तिगत बैठकें कीं और उनसे सीधे फीडबैक लिया।
सांसदों को जमीनी स्तर पर राज्य सरकार की विफलताओं को आक्रामक तरीके से उजागर करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, स्थानीय मुद्दों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जोन-वार आंदोलन शुरू करने को कहा गया है। रणनीति यह है कि इन आंदोलनों को विधानसभा चुनाव तक लगातार सक्रिय रखा जाए।
भाजपा सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनावों तक सांसदों से नियमित फीडबैक लिया जाता रहेगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शरद पवार ने सुनेत्रा से मुलाकात की

बारामती (महाराष्ट्र), 04 फरवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को परिवार के मुखिया के रूप में नरम रुख दिखाया। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के सवाल पर उन्होंने कहा कि

- इससे पहले उन्होंने अजित पवार के बेटों के साथ बंद कमरे में मीटिंग की थी।

कोई भी फैसला लेने से पहले अभी एक-दूसरे का साथ देना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कुछ दिन पहले उन्होंने रास्ता बंद (रोड ब्लॉक) वाला बयान दिया था।
शरद पवार ने दिवंगत अजित पवार के बेटों से बंद कमरे में मुलाकात की। इसके बाद वह बारामती में सुनेत्रा पवार के घर गए तथा अजित पवार को श्रद्धांजलि दी।
वरिष्ठ नेता शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी की कट-ऑफ पर नोटिस जारी किये

नयी दिल्ली, 4 फरवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-पीजी 2025-26 की परीक्षा के लिए कट-ऑफ परसेन्टाइल कम करने के राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड के निर्णय को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका

- राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड ने 13 जनवरी को कट-ऑफ परसेन्टाइल असामान्य रूप से कम कर दिया था।

पर बुधवार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने इस चुनौती पर गौर किया और निर्देश दिया कि मामले को छह फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
याचिका में परीक्षा बोर्ड की 13 जनवरी की उस अधिसूचना पर सवाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 फरवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले की पैरवी स्वयं की। उन्होंने राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेसिव रीविजन (एसआईआर) के खिलाफ दायर अपनी याचिका के समर्थन में दलीलें दीं।
ममता बनर्जी एक प्रशिक्षित अधिवक्ता हैं और वे पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन गई हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले पर खुद बहस की। इसके लिए उन्होंने अदालत में एक अंतरिम आवेदन दायर कर अनुमति मांगी थी।
ममता लंबे समय से राज्य में

- ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर इसकी अनुमति मांगी थी। ज्ञातव्य है कि ममता बनर्जी ने कहा था कि वे खुद एक वकील हैं और एसआईआर पर अपना केस खुद लड़ींगी।
- ममता बनर्जी लम्बे समय से एसआईआर का विरोध कर रही हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव, 2025 की मतदाता सूची पर ही होने चाहिए।
- ममता बनर्जी ने एसआईआर में भारी विसंगतियों का आरोप लगाया और कहा कि कई महिलाओं के नाम इसलिए हटा दिए क्योंकि उन्होंने विवाह के बाद भारतीय परम्परा के तहत पति का सरनेम लगाना शुरू कर दिया था।
- सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि एसआईआर के संबंध में गणमान्य व्यक्तियों को नोटिस भेजते समय सावधानी बरते। ज्ञातव्य है कि चुनाव आयोग ने पूर्व नौसेना एडमिरल अरूण प्रकाश, नोबल विजेता अमर्त्य सेन व क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी नोटिस भेजे हैं।

एसआईआर अभियान का विरोध करती रही हैं और चाहती हैं कि आगामी मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित जाए।

उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि असम में, जो एक भाजपा-शासित राज्य है, एसआईआर प्रक्रिया क्यों नहीं कराई गई।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर 4 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी और मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित हुई। दावे और आपत्तियां दर्ज

कराने की अंतिम तिथि 19 जनवरी थी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी की प्रकाशित होने की उम्मीद है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रगति को

देखते हुए समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।

उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अनमैड मतदाताओं का हवाला दिया और कहा कि सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बहुत कम समय बचा है।

बार एण्ड बैच ने दीवान के हवाले से कहा, अनमैड मतदाता 32 लाख हैं। तार्किक विसंगति सूची में 1.36 करोड़ नाम हैं और 63 लाख मामलों की सुनवाई लंबित है।"
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दो याचिकाओं में नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

अपनी नम्रता का गर्व करने से अधिक निंदनीय और कुछ नहीं है। –मारकस

जनमानस में रियासती उपाधियों की पुनर्स्थापना: अतिरंजित और अंतर्विरोधों से भरा विमर्श

जनमानस में रियासती उपाधियों की पुनर्स्थापना – यह शीर्षक अपने आप में ही विरोधाभासों से भरा हुआ है। आखिर इस कथित प्रयास के पीछे कौन है? निश्चय ही कोई लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार तो नहीं। और यह भी विचित्र है कि 'जनमानस' को इतना भोला और मूर्ख क्यों दिखाया जा रहा है? आज़ादी के सात दशक बाद क्या सचमुच यह मान लिया जाए कि जनता को इतनी आसानी से बहकाया या ब्रेनवॉश किया जा सकता है कि वह पुराने राजसी प्रतीकों को स्वीकार कर ले, जबकि लोकतांत्रिक मूल्य समाज के हर वर्ग में गहराई से जड़ें जमा चुके हैं? क्या जनता को इतना भी श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए कि वह स्वयं समझदार है, बजाय इसके कि उसे बिना विवेक और स्वतंत्र चिंतन वाले बच्चों की तरह पेश किया जाए?

लेखक अपने लेख की शुरुआत संविधान का हवाला देकर करते हैं समानता, समान अधिकार और यह सिद्धांत कि कोई भी किसी से ऊपर नहीं है। ठीक है, यह बात स्वीकार्य और निर्विवाद है। लेकिन इसके बाद वे चतुराई से प्रजामंडल आंदोलन को सामने ले आते हैं और उसे जनसाधारण द्वारा लड़ा गया एक दीर्घ संघर्ष बताते लगते हैं। यहीं समस्या शुरू होती है। इतिहास की सामान्य समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि प्रजामंडल आंदोलन कुछ गिने-चुने अभिजात, संपन्न और उच्चवर्णीय वर्गों द्वारा संचालित था, जो स्वयं मौजूदा सत्ता में भागिदार थे एवं अब उस सत्ता पर पूर्णतः काबिज होना चाह रहे थे। यह आंदोलन मुख्यतः कुछ शहरी केंद्रों तक सीमित रहा और इसमें व्यापक जनभागीदारी लगभग नहीं के बराबर थी।

इस तरह प्रजामंडल आंदोलन का उल्लेख करके लेखक राजस्थान की आबादी के एक विशेष वर्ग को निरंकुश और दमनकारी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। मेरे विचार में यह एक कमजोर तर्क है, जो प्राथमिक ऐतिहासिक जांच भी नहीं झेल सकता।

लेखक पूर्वशाही परिवारों के लिए हिज हाईनेस जैसी उपाधियों के प्रयोग पर आपत्ति जताते हैं और तर्क देते हैं कि ऐसी संबोधन शैली मूलतः अपमानजनक है और बोलने वाले को संबोधित व्यक्ति से हीन दर्शाती है। लेकिन यह दावा एक समस्याग्रस्त मान्यता पर आधारित है-कि इन उपाधियों का प्रयोग थोपा गया है। वास्तव में किसी को इन्हें इस्तेमाल करने के लिए बाध्य करने वाली कोई दमनकारी व्यवस्था मौजूद ही नहीं है; इनका प्रयोग अनिवार्यता नहीं, बल्कि एक स्वेच्छिक चयन है।

राजसी उपाधियों का निरंतर प्रयोग राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिघटना के रूप में बेहतर समझा जा सकता है। अनेक लोगों के लिए ये उपाधियाँ वंश, स्मृति और ऐतिहासिक निरंतरता के प्रतीक हैं, जो स्थानीय इतिहास और सामूहिक पहचान में रची-बसी हैं। इन्हें दर्शना भाव से नहीं, बल्कि उस विरासत की पहचान के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे आधुनिक सामाजिक-राजनीतिक अभिजात वर्ग को अस्थायी सत्ता की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है।

एयर इंडिया के लोगों में महाराजा जैसे सांस्कृतिक प्रतीक इस बात को और स्पष्ट करते हैं। यह छवि किसी दासवत् दण्डवत होने का प्रतीक नहीं, बल्कि राजत्व की उस परंपरागत धारणा से जुड़ी है जिसमें संरक्षण, संरक्षणदाता-भाव और शासक तथा प्रजा के बीच पारस्परिक दायित्व पर बल दिया जाता था। लोकप्रिय कल्पना में इसका टिके रहना सामाजिक-राजनीतिक ऊंच-नीच का समर्थन नहीं अपितु सांस्कृतिक स्मृति की निरंतरता को दर्शाता है।

इसलिए पारंपरिक उपाधियों के प्रयोग को झूठी चेतना या आंतरिक दासता का प्रमाण नहीं समझना चाहिए। इसके बजाय यह अतीत से निरंतरता बनाए रखने का स्वेच्छिक प्रयास है, जिसके माध्यम से लोग आधुनिक राजनीतिक सत्ता की नैतिक और सांस्कृतिक उथलापन से असंतोष भी व्यक्त करते हैं।

यह भी समझना आवश्यक है कि सामंत प्रतीक केवल पूर्वशाही परिवारों की उपाधियों तक सीमित नहीं है। वे राजस्थान की ऐतिहासिक पहचान और वैश्विक प्रस्तुति को आकार देने वाली भौतिक, सांस्कृतिक और संस्थागत विरासतों के व्यापक दायरे में फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के छह पहाड़ी किले, जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, केवल स्थापत्य अवशेष नहीं, बल्कि पूर्व-आधुनिक राजनीतिक संगठन, सैन्य रणनीति और सांस्कृतिक संरक्षण के स्थायी प्रतीक हैं।

इसी प्रकार जयपुर शहर, जिसे यूनेस्को ने प्रांरिक आधुनिक शहरी नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण माना है, प्रत्यक्ष रूप से राजकीय पहल और शासकीय स्थापत्य दृष्टि से उत्पन्न हुआ। इसकी योजनाबद्ध ग्रीड संरचना, नागरिक स्थल और खगोलीय-प्रशासनिक सिद्धांतों का समन्वय इस धारणा को चुनौती देता है कि रियासती राज्य स्वभावतः जड़ और पिछड़े थे।

भाषायी और साहित्यिक परंपराएँ भी सामंतवाद की आलोचना को जटिल बनाती हैं। राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ दरबारी और प्रशासनिक संदर्भों में विकसित और मानकीकृत हुईं। डिंगल और पिंगल साहित्य, जिसे आधुनिक इतिहासलेखन में अक्सर उपेक्षित किया जाता है, वह राजकीय संरक्षण से समृद्ध हुआ और उच्च भारतीय साहित्यिक परंपरा में योगदान दिया। इसी प्रकार राजस्थानी चित्रकला की प्रसिद्ध परंपराएँ भी अभिजात और राजकीय संरक्षण की देन हैं, जिन्हें आज विश्वभर के संग्रहालयों और अकादमिक जगत में सराहा जाता है।

यहाँ एक वैचारिक विरोधाभास उभरता है। जब राज्य और राष्ट्र स्वयं इन सांस्कृतिक प्रतीकों को धरोहर पर्यटन, राष्ट्रीय ब्रांडिंग और सॉफ्ट पावर के लिए उपयोग करते हैं, तब उन्हीं प्रतीकों को संरक्षित करने वाले सामंत वर्ग को नैतिक रूप से खारिज करना विश्लेषणात्मक रूप से असंगत प्रतीत होता है। यह दृष्टिकोण सामंतवाद का महिमामंडन करने या उसकी असमानताओं को अनदेखा करने का आग्रह नहीं करता, बल्कि यह कहता है कि सामंत संस्थाओं को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाए और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन उनकी सीमाओं के साथ किया जाए, न कि आधुनिक मापदंड से उन्हें एकरेखीय रूप से खारिज किया जाए।

लेखक लोकप्रिय संस्कृति में राजसी ठाट-बाट के चित्रण से असहज महसूस करते हैं, लेकिन यह स्वीकार नहीं करते कि ऐसी प्रस्तुतियाँ आधुनिक पूंजीवादी बाजार की उपज हैं, न कि सामंती स्मृति की। क्या बिकता है, यह बाजार तय करता है, न कि भूतपूर्व राजपरिवार। यह प्रवृत्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्वभर में ऐतिहासिक और राजसी ड्रामा लोकप्रिय हैं- डाउनउन एबे से द क्राउन तक और गेम ऑफ़ थ्रोन्स से द टयूयूड्स तक। उनका आकर्षण सत्ता समर्थन नहीं, बल्कि दृश्यात्मक भव्यता और कथा-निर्माण में है। विश्व भर में जापान, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन जैसे प्रागैतिहासिक देशों में सर्वेधानिक राजतंत्र हैं। जबकि भारत में राजकीय उपाधियाँ केवल सांस्कृतिक हैं, क्योंकि राजाओं ने स्वेच्छा बदलते राजनैतिक परिवेश को देख भारत में राजनैतिक विलय करके अपनी राजनैतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित करने में सहयोग किया। किन्तु क्या आधुनिक जोधपुर में गजसिंघजी या आधुनिक जयपुर में ब्रिगिडियर भवानी सिंघजी के योगदान को नकारा जा सकता है ? यह चिंता कि दर्शक राजसी सौंदर्यशास्त्र से मोहित हो जाएंगे, दर्शकों को कमतर बुद्धिमान मानने की पितृसत्तात्मक धारणा पर आधारित है, मानो वे इतिहास, कल्पना और राजनीतिक समर्थन में फर्क नहीं कर सकते।

लेख का मूल स्वर एक विशिष्ट वर्ग के प्रति वैचारिक शत्रुता से प्रेरित लगता है। जयपुर लितरेचर फेस्टिवल द्वारा किसी व्यक्ति को पूर्वशासक कहने जैसी सामान्य सांस्कृतिक औपचारिकता को लेखक ने लगभग सवैधानिक संकेत जैसा बना दिया जो वास्तव में पिछड़ा पर विवादित टॉपिंग जितना ही गंभीर मुद्दा था। अंततः यह लेख गंभीर वैचारिक व सांस्कृतिक आलोचना से अधिक वैचारिक अतिरेक का अभ्यास प्रतीत होता है, जहाँ ऐतिहासिक संदर्भों के सामान्य उल्लेख को सभ्यतागत पतन के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कथित खतरे और वास्तविक घटना के बीच असंगति इतनी स्पष्ट है कि यदि लेख से गंभीरता का आवरण हटा दिया जाए, तो यह ज़ेनोफोबिया से उपजी एक हास्यास्पद अतिशयोक्ति भर है ।

– अतिथि संपादक
एल के सिंह,
(डॉक्टर और सामाजिक टिप्पणीकार)

परीक्षा की शुचिता बनाम कक्षा की गुणवत्ता: डिजिटल निगरानी का असंतुलन और प्रस्तावित समाधान



प्रो.अशोक कुमार

भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था आज एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रही है। एक ओर हम डिजिटल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी आज भी इस बात पर केंद्रित है कि छात्र परीक्षा के तीन घंटों में नकल न कर पाए। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है, फ्लाईंग स्वायद्व तैनात किए जाते हैं और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग केवल दंडात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल परीक्षा की निगरानी कर लेने से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी? सच तो यह है कि परीक्षा की शुचिता की चिंता तब की जाती है जब कक्षा की गुणवत्ता दम तोड़ चुकी होती है। यदि छात्र को साल भर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं मिला, तो वह परीक्षा में अनैतिक रास्तों की ओर मुड़ता ही है। यह लेख इस बात की वकालत करता है कि तकनीक का उपयोग केवल परीक्षा

केंद्रों पर नहीं, बल्कि साल भर चलने निगरानी नहीं, बल्कि एक शैक्षणिक इन्वेंट्री होगी जो बताएगी कि संसाधनों का कितना उपयोग हो रहा है।

2. संसाधनों का इष्टतम उपयोग और प्रशासनिक जिम्मेदारी

सरकारें करोड़ों रुपये खर्च करके कॉलेजों में स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और लैब स्थापित करती हैं। अक्सर देखा गया है कि ये संसाधन धूल फांकते रहते हैं या केवल निरीक्षण के दिन ही बाहर निकलते हैं। डिजिटल ऑडिट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकारी धन का उपयोग वास्तव में छात्रों के हित में हो रहा है।

3. शैक्षणिक जवाबदेही और उपस्थिति

अक्सर दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की अनुपस्थिति एक बड़ी समस्या है। डिजिटल निगरानी शिक्षकों को उनकी उपस्थिति और शिक्षण के प्रति जवाबदेह बनाएगी। जब शिक्षकों को पता होगा कि उसकी कक्षा का ऑडिट किया जा सकता है, तो शिक्षण की गुणवत्ता और गंभीरता में स्वतः ही सुधार होगा।

डिग्री वितरण बनाम ज्ञानार्जन

वर्तमान में बिना पढ़ाई के डिग्री बांटने की जो प्रथा चल पड़ी है, उसने भारतीय युवाओं की वैश्विक साख को खतरे में डाल दिया है। जब कक्षाएं नियमित नहीं होतीं, तो छात्र केवल पास होने के लिए रट्टा मारते हैं या नकल का सहारा लेते हैं। इस प्रक्रिया में डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन योग्यतागम्य रह जाती है। कक्षा की डिजिटल निगरानी इस डिग्री मिल संस्कृति पर प्रभावी लगाम लगाएगी।

डिजिटल राजस्थान में बढ़ता अकेलापन



भूपेश दीक्षित

राजस्थान आज डिजिटल क्रांति के दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। 'पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स' रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2026 तक राजस्थान में 10 से 29 वर्ष आयु वर्ग की आबादी लगभग 3 करोड़ होगी। यह वह पीढ़ी है जिसके हाथों में प्रदेश का आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी

भविष्य होगा। लेकिन डिजिटल गंधी के इस उजले पहलू के साथ एक अंधरा चुनौती भी तेजी से उभर रही है। आज के युवा अपना अधिकांश समय स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और स्कॉलिंग में बिता रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी नींद, एकाग्रता, पढ़ाई, कार्यक्षमता और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। डिजिटल कंटेंट कंपनियाँ ऐसे अल्ट्राथिन बना रही हैं जो बच्चों और युवाओं को घंटों स्क्रीन से बांधे रखते हैं। समस्या तकनीक के उपयोग की नहीं बल्कि उसके अतिरिंत्रित और व्यसनी स्वरूप की है। ऑनलाइन शॉपिंग, रील्स, लाइक्स, कमेंट्स और स्टेटस अपडेट जैसी गतिविधियाँ ने युवाओं को आभासी दुनिया में तो जोड़ दिया है लेकिन वास्तविक समाज से दूर कर दिया है। परिणामस्वरूप अकेलापन, तनाव, अवसाद, भावनात्मक अस्थिरता और आत्महत्या के विचार तेजी से बढ़ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य संकेत अब केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं रह गया बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती

बन चुका है। राजस्थान राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2024 में प्रदेश में 5530 लोगों की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई यानी औसतन हर दिन लगभग 15 परिवार इस दर्द से गुजर रहे हैं। ये आंकड़े केवल संख्याएँ नहीं बल्कि टूटते सामाजिक ताने-बाने की चेतावनी हैं।

इसी पृष्ठभूमि में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश देता है। सर्वेक्षण बताता है कि जिन राज्यों और उनके जिलों में जहाँ सामाजिक जुड़ाव मजबूत है जैसे- बिहार और उत्तरप्रदेश, वहाँ आत्महत्या की दर कम है। वहीं जिन राज्यों में लोग परिवार और समुदाय से भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं जैसे- केरल और तमिलनाडु, वहाँ आत्महत्या दर अधिक है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि डिजिटल कनेक्टिविटी मानवीय रिश्तों का विकल्प नहीं बन सकती।

राजस्थान के कोटा, सीकर और जयपुर जैसे शैक्षणिक केंद्रों में लाखों विद्यार्थी घर से दूर रहकर पढ़ते हैं। उनके पास ऑनलाइन संपर्क तो है लेकिन

भावनात्मक सहारे का अभाव है जो अक्सर गहरे मानसिक तनाव को जन्म देता है और जिसके दुष्परिणाम हमें आत्महत्या के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन पर मिलने वाली क्षणिक सराहना वास्तविक अपनत्व का स्थान नहीं ले सकती। इस चुनौती से निपटने के लिए केवल काउंसलिंग अथवा हेल्थलाइन रॉपॉप नहीं है। जरूरत है व्यापक सामाजिक और शैक्षणिक हस्तक्षेप की जैसे स्कूलों में मेंटल एंड डिजिटल वेलनेस कार्यक्रम, मेंटरशिप प्रणाली, बुद्धि सिस्टम, सहायी सहयोग समूह, खेल-कला गतिविधियाँ और परिवारों में खुला संवाद।

समस्या के समाधान हेतु आगामी राज्य बजट में तीन ठोस प्रमाण आधारित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार, स्कूल-कॉलेज आधारित काउंसलिंग सेवाओं और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रावधान। दूसरा, मेंटल हेल्थ एंड डिजिटल वेलनेस मिशन के तहत शिक्षक प्रशिक्षण और अभिभावक जागरूकता अभियान

और तीसरा, युवा साथी केंद्रों और नेहरू युवा केंद्रों को मजबूत कर सामुदायिक संवाद और परामर्श की सुविधाओं में विस्तार।

राजस्थान के पास टेली-मानस, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ प्रोताम और युवा साथ केंद्र जैसी व्यवस्थाएँ पहले से मौजूद हैं। आवश्यकता बस इतनी है कि नीति और बजट दोनों के केंद्र में सामाजिक जुड़ाव को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि जीवन बचाने का सबसे बड़ा सहारा दवाइयाँ, मोबाइल, इंटरनेट या डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं बल्कि मजबूत रिश्ते, सच्ची बातचीत और संवेदनाशील समाज हैं। सरकार द्वारा जनहित में उठाये जाने वाले इन्ही ठोस कदमों से आयुष्मान स्वस्थ राजस्थान और विकसित राजस्थान 2047 का सपना साकार होगा।

–भूपेश दीक्षित,
जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं
संयोगक्षेत्र, द राजस्थान मेंटल
हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन
नेटवर्क, जयपुर (राजस्थान)

खेजड़ी बचाओ आंदोलन - अनशन पर बैठे संत की तबीयत बिगड़ी

- **लोगों ने खुद को रेलिंग से बांधा; संत बोले-कानून नहीं बना तो हालत खराब कर देंगे**
- **अनिश्चितकालीन अनशन तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा**

बैठे हैं। उन्होंने निर्णय होने तक पट्टी न खोलने की बात कही है। आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि मांगों पर ठोस फैसला होने तक अनशन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। कलेक्ट्रेट और बिशोई धर्मशाला के बाहर पुलिस के करीब डेढ़ हजार जवान कड़ी निगरानी कर रहे हैं। वहीं, बिशोई धर्मशाला में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है।

तबीयत बिगड़ने पर अनशनकारी मांगीलाल नोखड़ा को एम्ब्यूलेंस से पीबीएम हॉस्पिटल ले जाते लोग। बीकानेर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। अन्न-जल त्यागकर बैठे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। कानून नहीं बना तो हालत खराब कर देंगे। बस तारीख बता दो, आमरण अनशन खत्म कर चले जाएंगे।

अनशन के दौरान पर्यावरण प्रेमी महेंद्रकुमार आंखों पर पट्टी बांधकर

चेकअप कर रही है। बीकानेर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। संतों की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया है। एडिशनल एसपी (सिटी) चक्रवर्ती सिंह और एडिशनल एसपी (ग्रामीण) बनवारी लाल दोनों ही अनशन स्थल के आसपास ही तैनात हैं। एसपी कावेंद्र सिंह सागर का कहना है कि स्थिति को देखते हुए कलेक्ट्रेट और धरना स्थल पर करीब डेढ़ हजार जवानों की तैनाती की गई है।

आंदोलन से जुड़े विक्रम बिशोई ने बताया कि धरना स्थल पर 24 घंटे से अधिक समय से अनशनकारियों ने पानी तक नहीं पीया है। कई अनशनकारियों की उम्र 70 साल से

अधिक है, ऐसे में उनकी तबीयत भी नाजुक हो गई है। संत लाल दास महाराज भी डि-हाइड्रेट होकर बेहोश हो गए थे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उनका सीटी स्कैन किया जाएगा। हमें विश्वास है कि किसी के साथ कुछ गंभीर नहीं हो। धरना स्थल पर अनशनकारी मांगीलाल नोखड़ा की भी तबीयत बिगड़ चुकी है। उनका बीपी 300 तक पहुँच गया है। उन्हें भी एम्ब्यूलेंस से पीबीएम हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। अनशनकारियों की संख्या को देखते हुए बिशोई धर्मशाला में ही एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक देवेंद्र चौधरी ने बताया- 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ तैयार किया जा रहा है। अब तक 50 से ज्यादा बेड लगा चुके हैं। सीएमएचओ डॉ. पुष्कराज साध का कहना है कि सभी मरीजों को चेक किया जा रहा है। जिनकी जरा भी तबीयत कमजोर लग रही है, उन्हें भर्ती किया जा रहा है।

फलोदी जिले से आए श्यामलाल

का कहना है कि मैंने जिला कलेक्टर के माध्यम से रिफर्मेंट की पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि मेरे समाज के संत आमरण अनशन पर बैठे हैं। यह मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं राष्ट्रपति से कहना चाहता हूँ कि या तो वे संत-महात्माओं का आमरण अनशन खत्म करवाएँ या फिर मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दें। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न लें। श्रीगंगागंग किसान संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष अमर सिंह बिशोई ने कहा कि गूंगी-बहरी सरकार को जगाने के लिए उन्हें यह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूमकर रेलवेज वार्मिंग का संदेश दे रहे हैं। जब दुनिया को पर्यावरण के महत्व की जानकारी भी नहीं थी, तब यहां के लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने निराला दिए थे।

प्रशासन किसी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड है। अनशन पर बैठे लोगों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। मेडिकल टीम मौके पर ही स्वास्थ्य जांच कर रही है।



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल
गुरुवार 5 फरवरी, 2026
फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत 2082, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:57 तक, सुक्रमां योग रात्रि 12:04 तक, बव करण दिन 12:16 तक, चन्द्रमा कन्या राशि में संचार करेगा।
गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज शुक्र कुम्भ राशि में रात्रि 1:11 पर प्रवेश करेगा। आज चतुर्थी व्रत है। चन्द्रोदय जयपुर में रात्रि 9:41 पर होगा।
श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:36 तक, चर 11:19 से 12:41 तक, लाभ-अमृत 12:41 से 3:24 तक, शुभ 4:46 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 6:07

मेघ
स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अनहोनी की आशंका से बचा हुआ मन का भय दूर होगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा।

वृश्चिक
आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

मिथुन
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कर्क
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेगे। घर-परिवार में चल रही अपसी मतभेद दूर होंगे।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बन्ते कार्य बिगड़ सकते हैं। व्यावसायिक/पारिवारिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में आज उचित सफलता मिलेगी। अटक हुए कार्य बनने लगेगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

मीन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में “गाली” निकाली

मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस पर आपत्ति जताई तो सभापति ने अपशब्दों को सदन की कार्यवाही से हटवाया

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर। पूर्व यूडीएच मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में “गाली” निकाल दी। जिस पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति जताई, इसके बाद सभापति ने उनके द्वारा बोले गए अपशब्दों को सदन की कार्यवाही से बाहर निकलवाया।

दरअसल धारीवाल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कहा था कि “अगर लाखों युवाओं को शिक्षा देने के लिए रोजगार योग्य नहीं बनाया तो यह युवा आबादी चुनौती बन जाएगी।” उनके इस बयान के बीच सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा “इस देश में एक युवक को छोड़कर सबको रोजगार मिल गया।” इस दौरान गर्ग को जवाब देते हुए धारीवाल ने कहा, आपकी बात आधी समझ आती है...लेकिन आधी नहीं। इसी दौरान धारीवाल ने गर्ग को संबोधित करते हुए गाली निकाल दी।

धारीवाल की बात खत्म करने के बाद सरकारी मुख्य सचेतक ने खड़े होकर आपत्ति जतायी। उन्होंने कहा कि आदत के मुताबिक धारीवाल ने आज सदन में फिर्त गाली दी है, उसे सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। जिस पर सभापति ने गाली को कार्यवाही से हटाने के

- इससे पूर्व धारीवाल ने प्रधानमंत्री कौशल योजना में 10 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया।
- उन्होंने सड़कों के मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री दीपा कुमारी द्वारा सदन में दिए गए जवाब में भी झूठ बोलने के आरोप लगाए

आदेश दिए। ज्ञात रहे कि शांति धारीवाल पहले भी सदन में गाली दे चुके हैं, उस वक़्त भारी हंगामा हुआ था और उन्हें सदन से माफ़ी मांगनी पड़ी थी।

इससे पहले शांति धारीवाल ने जहां प्रधानमंत्री कौशल योजना में 10 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। वहीं सड़कों के मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री दीपा कुमारी पर भी सदन में झूठ बोलने के आरोप लगाए। धारीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल योजना को लेकर सीएनडी ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें 10 हजार करोड़ के घोटाले की बात कही है।

रिपोर्ट में एक करोड़ 32 लाख में से 95 प्रतिशत लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं। धारीवाल ने

आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से फर्जी स्किल सेंटर खुलवा दिए हैं, इसलिए घोटाला किया गया है। बैंक खातों का कोई विवरण नहीं है, फर्जी फोटो और फर्जी फिंगरप्रिंट और एक मोबाइल नंबर से लाखों लोगों को भुगतान किया गया है। धारीवाल ने कहा कि जिन युवाओं ने आपको सत्ता में बैठाया है, कल वही आपके लिए चुनौती बन सकते हैं।

हमारे कार्यकाल में 70 हजार किमी सड़कें बनीं

शांति धारीवाल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री दीपा कुमारी ने सदन में कहा है कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में 13,160 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो 2024-25 में आई थी, उसमें पेज नंबर 12 पर लिखा है कि कांग्रेस के शासन में 70 हजार किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं। धारीवाल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सदन में झूठ बोला है।

धारीवाल ने कहा कि भाजपा के 2 साल के शासन में 14,800 किलोमीटर की सड़क बनाने की बात कही गई है, जबकि हमारी सरकार के दो साल के शासन में ही 23 हजार 585 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। यह भी

पीडब्ल्यूडी की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इस तरह से झूठे भाषण सदन में नहीं देना चाहिए था।

नाम हटाने से विचारधारा खत्म नहीं होगी

धारीवाल ने कहा कि भाजपा की सरकार ने एक-एक करके हमारी सारी योजनाओं के नाम बदल दिए हैं और अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। हमने जो योजनाएं शुरू की थीं, उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि वो गरीबों, छात्रों और मजदूर किसानों के हित की योजनाएं थीं। मनरेगा में ग्राम सभा का अधिकार केंद्र सरकार ने छीन लिया है।

शांति धारीवाल ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को दुनिया से हटाया, लेकिन केंद्र सरकार ने अहिंसा के आविष्कार करने वाले महात्मा गांधी का नाम ही योजनाओं से हटाना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि “महात्मा गांधी का नाम दुनिया की जवान, दुनिया के दिल और दुनिया के दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। महात्मा गांधी की मूर्तियां 80 देशों में लगी हुई हैं, लाखों की तादाद में लोग उनके दर्शन करने आते हैं।”

“खेजड़ी बचाओ” आंदोलन का मुद्दा विधानसभा में गूंजा

कांग्रेस विधायक डूंगरराम ने कहा कि “लाखों लोग महापड़ाव में बैठे हैं, 29 संत और 339 पुरुष आमरण अनशन पर हैं, इसके बावजूद राज्य सरकार ने किसी से वार्ता नहीं की।”

जयपुर (विर्स)। विधानसभा में शून्यकाल में पर्वों के जरिए मामला उठाते हुए कांग्रेस विधायक डूंगर राम गेदर ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण बचाओ, खेजड़ी बचाओ समिति बिस्नोई समाज की अगुवाई में पिछले दो साल से बीकानेर में आंदोलनरत है, लेकिन खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई उसके बावजूद भी हो रही है। खेजड़ी राज्य वृक्ष है, इसे बचाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। गेदर ने कहा कि सरकार को पता था इसके बावजूद आंदोलनकारियों से कोई बातचीत नहीं की।

लाखों लोग महापड़ाव में आए। आज तीसरे दिन भी 29 संत अन्न, जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठे हैं। करीब 339 पुरुष अन्न,जल त्याग कर बीकानेर में आमरण अनशन पर बैठे हैं। तीन धरतीधियों की तबीयत खराब हो चुकी है, कोई सरकार का प्रतिनिधि वहां

- नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने भी कहा कि “साधु संत धरने पर बैठे हैं, सरकार की इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि उनसे बातचीत करें”

पर नहीं गया। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने कहा कि साधु संत धरने पर बैठे हैं। सरकार की इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि उनसे बातचीत करें। खेजड़ी राज्य वृक्ष नहीं देव वृक्ष भी है, लोग पूजते हैं। आप लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं। कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर ने कहा कि 10 नवंबर 2024 को जब बिस्नोई समाज ने राष्ट्रीय स्तर पर खेजड़ी बचाने के लिए महापड़ाव

डाला था। उस समय खीवसर का उपचुनाव था। सरकार को लगा कि खीवसर का चुनाव हार रहे हैं, इसलिए 9 नवंबर 2024 को कुचेरा में बिस्नोई समाज के साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई। खेजड़ी पर सख्त कानून बनाने का आश्वासन दिया गया। चुनाव निकल गया, चुनाव जीत लिया, मुझे को जुमले की टोकरी में डाल दिया गया, कानून क्या बनाना था।विधायक डूंगरराम ने कहा कि, एक साल बाद संसदीय कार्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेड़ काटने पर 100 रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा वन विभाग की लकड़ी काटने पर जो 6 महीने की सजा थी, उसकी जगह मात्र 5000 रुपए जुर्माना कर दिया जाएगा, जिससे उद्योगपतियों को खेजड़ी काटने की और आसानी से परमिशन मिल गई। आप उद्योगपतियों के आगे इतना झुकते क्यों हैं?



जयपुर। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सेवानिवृत्त उपनिदेशक डॉ. लीलाधर दोचानिया के नव प्रकाशित कविता संग्रह “जिन्दगी मुस्कुराते रहे” का विमोचन शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। विमोचन वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक त्रिलोक चंद कौशिक करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित साहित्य संगीत और चित्रकला के त्रिआयामी उत्सव पिकनफेस्ट के दौरान महाराष्ट्र के वरिष्ठ साहित्यकार मनीषा खटाते सहित विभिन्न स्थानों के अनेक लेखक भाग लेंगे। संयोजन सीमा वालिया करेंगी।

भजनलाल सरकार ने मजबूत की प्रदेश में महिला सुरक्षा : बेढ़म

जयपुर। राजस्थान 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र के दौरान बुधवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से रूबरू होते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने प्रदेश में महिला अपराधों की स्थिति, कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर विस्तृत जानकारी दी।

मंत्री बेढ़म ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और अपराधों में कमी देखने को मिली है। गृह राज्य मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2019 में महिला अत्याचार के 41 हजार 155 प्रकरण दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2023

में यह संख्या 42 हजार 174 रही। इसके बाद वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रभावी पुलिस कार्रवाई और संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था के कारण वर्ष 2024 में प्रकरण घटकर 37 हजार 700 रह गए तथा वर्ष 2025 में 37 हजार 981 प्रकरण दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि यह कमी पुलिस

द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, त्वरित अनुसंधान और सरकार की प्राथमिकताओं का परिणाम है।

उन्होंने बताया कि अनुसंधान अधिकारियों को 60 दिवस की निर्धारित अवधि में जांच पूरी कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश हैं।

थाईलैंड की राजकुमारी 6 से 10 फरवरी तक रहेंगी राजस्थान प्रवास पर

मुख्य सचिव ने की रॉयल थाई एम्बेसी की एम्बेसडर चवनाई थांगसुमफैट के साथ तैयारियों की समीक्षा

जयपुर (कासं)। थाईलैंड की राजकुमारी प्रिंसेस सिरिविवावरी नारिताना राजकन्या 6 से 10 फरवरी तक राजस्थान प्रवास पर रहेंगी। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उनकी यात्रा प्रवास को लेकर बुधवार को शासन सचिवालय में रॉयल थाई एम्बेसी की एम्बेसडर चवनाई थांगसुमफैट सहित थाई एम्बेसी और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान की पूरे विश्व में अतिथि देवो भवः की परंपरा की अपनी अनूठी पहचान है। ऐसे में प्रिंसेस सिरिविवावरी नारिताना राजकन्या की मेहमान नवाजी का अवसर मिलना राज्य के लिए हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि थाई राजकुमारी का यह दौरा भारत-थाईलैंड संबंधों में और अधिक गहरे सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहित करेगा।

मुख्य सचिव ने प्रिंसेस की यात्रा के दौरान पुलिस तैयारियों, सुरक्षा तैयारियों, यातायात व्यवस्था, प्रोटोकॉल, संबंधी समस्त पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। प्रिंसेस सिरिविवावरी नारिताना राजकन्या अपने प्रवास के दौरान जयपुर एवं जोधपुर का भ्रमण करेंगी। जयपुर में वे आमेर किला, हवामहल, सिटी पैलेस, त्रिपालिया बाजार सहित अन्य प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का अवलोकन करेंगी। इसके पश्चात जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, उममेद पर्वत, चामर पैलेस, जसवंत थड़ा सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण प्रस्तावित है। इस दौरान उन्हें राजस्थान की समृद्ध हस्तशिल्प कला, शिल्पकला, संस्कृति,



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने थाईलैंड की राजकुमार के राजस्थान यात्रा प्रवास को लेकर बुधवार को सचिवालय में बैठक ली। उन्होंने रॉयल थाई एम्बेसी की एम्बेसडर चवनाई थांगसुमफैट सहित थाई एम्बेसी और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ तैयारियों पर चर्चा की।

विरासत एवं पारंपरिक आतिथ्य से भी अवगत कराया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग नवीन जैन, महानिदेशक पुलिस, (कानून एवं व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल, जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम, आयुक्त पर्यटन विभाग रूक्मणि

रियार, जयपुर कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के साथ थाई एम्बेसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इनके साथ ही पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह, जोधपुर कलेक्टर गौरव गोयल, जोधपुर पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े।

ग्राम उत्थान शिविरों में अब तक 77 लाख प्रकरण निस्तारित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास धरातल पर हो रहे साकार

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रामीणों तक सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित ग्राम उत्थान शिविरों में अब तक आमजन की 77 लाख से अधिक समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। अब 5 से 9 फरवरी तक ग्राम उत्थान शिविर का द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

गत 23 जनवरी (बंसंत पंचमी) से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर इन शिविरों का शुुरुआत की गई थी और इनसे किसान, पशुपालक, महिला एवं श्रमिक सहित विभिन्न वर्गों को एक ही छत के नीचे योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इससे प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी कम हुई है और आत्मनिर्भर एवं सशक्त ग्रामीण राजस्थान को गति मिली है।

इन शिविरों के तहत अब तक पूरे प्रदेश में एक हजार 512 शिविर लगाकर ग्रामीणों को राहत दी गई है। अब तक इन शिविरों में 13 लाख 91 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। जिसमें 9 लाख 17 हजार पुरुष एवं 4 लाख 12 हजार महिलाएं शामिल हैं। प्रत्येक

गिरदावर सर्किल पर आयोजित इन शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को 98 हजार 299 से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड और 55 हजार 886 स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। पशुपालकों के लिए भी इन शिविरों में अनेक कार्य करवाए जा रहे हैं। इन शिविरों में

- 5 से 9 फरवरी तक ग्राम उत्थान शिविर का द्वितीय चरण होगा

मंगला पशु योजना के तहत 92 हजार पशुपालकों का पंजीकरण किया गया तथा 5 लाख 11 हजार पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा और 77 हजार पशुओं का टीकाकरण किया गया है। शिविरों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 28 हजार 908 पंजीकरण तथा फार्मर रजिस्ट्री के 14 हजार 430 पंजीकरण किए गए हैं। शिविरों में फार्म पौड, तारबंदी, पाईपलाइन के आवेदन, प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण, नहरों एवं खालों की मरम्मत, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण का प्रचार-प्रसार, कृषि योजनाओं की जानकारी, मिनी किट वितरण का सत्यापन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, युवा स्वरोजगार योजना, ड्रिप, फव्वारा संयंत्र, प्लास्टिक मत्त के आवेदन सहित डेयरी, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं एवं योजनाओं के कार्य कराए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रति भारी उत्साह

- 10 दिनों में ही 5 हजार से अधिक लोगों ने किया आवेदन
- योजना में 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण
- 50 हजार रुपये तक मार्जिन मनी का प्रावधान

जयपुर (कासं)। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह है। करीब 10 दिनों में ही 5 हजार से अधिक प्राप्त हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी

को इस योजना का शुभारंभ किया था और 15 जनवरी को विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के प्रति युवाओं की बेहतर प्रतिक्रिया रही है। अब तक 5,089 लोगों ने आवेदन किया है, 22 जनवरी को आवेदन शुरू किए गए थे। जिला महाप्रबंधकों द्वारा इन आवेदनों की जांच

कर ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए शीघ्र ही बैंकों को अप्रेषित किए जाएंगे।

जयपुर जिले में सर्वाधिक 385 आवेदन

जयपुर जिले में सर्वाधिक 385 आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही, चूरू, बीकानेर, टोंक, और हनुमानगढ़ जिलों में 200 से अधिक आवेदन आए हैं। बूंदी, सीकर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, दौसा, रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।

सुनिश्चित कीजिए उनकी मुस्कुराहट प्लस सुरक्षा

एलआईसी का प्रोटेक्शन प्लस

प्लान सं.: 886 यूआईएन: 5121361101

पेश है

विशेषताएँ:

- ❖ आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनेक निवेश फंड विकल्प उपलब्ध
- ❖ अपनी जोखिम बीमा-सुरक्षा बढ़ाएँ, टॉप अप प्रीमियम भुगतानों के साथ
- ❖ आयु एवं अवधि के अनुसार उच्च बीमा राशि चुनने का विकल्प
- ❖ 5 वर्ष बाद आंशिक निकासी की अनुमति

एक नॉन-पार, लिक्विड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत प्लान

ऑनलाइन भी उपलब्ध

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 **कहिप 'Hi'** अधिक जानकारी के लिए आप अपने बीमा एजेंट/नजदीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें **लिंकड** **वेबसाइट** करें: www.licindia.in **कॉल सेंटर सर्विस** (022) 6827 6827

हम यहाँ फ़ोले करें: [f](#) [y](#) [X](#) [in](#) LIC India Forever IRDAI Regn No.: 512

भारतीय जीवन बीमा निगम **LIC** **हर पल आपके साथ**

छोछेछाड़ी वाली फ़ोन कॉलस तथा झूठे/भ्रामक प्रस्तावों से सावधान रहें। आईआरडीआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बीनस की घोषणा या प्रीमियमस के निवेश, राशियाँ लेटना जैसी कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। जिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फ़ोन कॉलस मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें। कृपया बिंदी के समान से पहले बिंदी पुस्तिका को ध्यान से पढ़ लें।

लिंकड इश्योरेन्स प्रोडक्ट्समिन् होते हैं पारंपरिक इश्योरेन्स प्रोडक्ट्स से तथा उनके साथ जोखिम घटक होते हैं। लिंकड इश्योरेन्स पॉलिसियों में अन्दा किए गए प्रीमियम पूंजी बाजार तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंडेक्स से जुड़े निवेश जोखिम होते हैं। फंड की कार्यकुशलता तथा पूंजी बाजार/सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंडेक्स को प्रभावित करने वाले घटकों के आधार पर युनिट्स के एन्वैजिज घट-बढ़ सकते हैं तथा बीमित व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम/लाइफ इश्योरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केवल जीवन बीमा कंपनी का नाम है तथा प्रोटेक्शन प्लस केवल लिंकड इश्योरेन्स संविदा का नाम है तथा किसी भी रूप में संविदा की गुणवत्ता, इसकी भावी संभावनाओं या आमदनीयों की ओर संकेत नहीं करता है। कृपया अपने बीमा एजेंट या मध्यावर्ती या इश्योरेन्स कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी दस्तावेज से संबंधित जोखिमों और लागू प्रसारों की जानकारी प्राप्त करें। इस संविदा के अंतर्गत पेश किए गए फिन्डस केवल फंड्स के नाम हैं तथा वे किसी भी रूप में इन प्लान्स की गुणवत्ता, उनकी भावी संभावनाओं तथा आमदनीयों की ओर संकेत नहीं करते हैं।

आवासहीन परिवारों की संख्या के सवाल पर मंत्री खर्चा और सुभाष गर्ग के बीच नौकझोंक

दरअसल प्रश्नकाल में आर.एल.डी. विधायक सुभाष गर्ग ने आवासहीन परिवारों की संख्या पूछी थी, लेकिन यू.डी.एच. मंत्री खर्चा पीएम आवास योजना को लेकर जवाब देने लगे थे

जयपुर (विसं)। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्चा भी सदन में विपक्ष के सवालों में उलझकर रह गए। प्रश्नकाल के दौरान विवाद की शुरुआत आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के सवाल से हुई। गर्ग ने भरतपुर में आवासहीन परिवारों की संख्या और पीएम आवास योजना के पात्र परिवारों पर सवाल पूछा था। सही जवाब नहीं मिलने पर विधायक सुभाष गर्ग ने आपत्ति जताई। जिस पर दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बहस और नौकझोंक होत रही।

मंत्री खर्चा के जवाब से असंतुष्ट सुभाष गर्ग ने कहा कि पहले

■ इस बीच अन्य मंत्रियों ने मंत्री के पक्ष में जवाब देने की कोशिश की तो नेता प्रतिपक्ष ने भी आपत्ति जताई

आवासहीन परिवारों की संख्या बताइए। जिस पर मंत्री खर्चा, पीएम आवास योजना की पात्रता की शर्तें बताते लगे। उनके जवाब पर गर्ग ने आपत्ति करते हुए कहा कि होमलेस पॉलिसी-2022 में आवासहीन परिवारों के सर्वे करने का

प्रावधान है या नहीं। मैंने तो इस पर जवाब मांगा था। मैं तो हां-ना में जवाब मांग रहा हूं।

जिस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्चा ने कहा कि भरतपुर में पीएम आवास योजना के 80 फीसदी पूरे हो चुके हैं। गर्ग ने कहा कि, भूमिहीन परिवारों की संख्या पर सवाल किया है। जिनके पास भूमि ही नहीं है वो आवासहीन कैसे होगा? आवासहीन तो उस दिन होगा जिस दिन भूमि होगी। जिसके पास जमीन नहीं है, वो तो बेघर कहलाएगा। आवासहीन नहीं। जिसके पास रहने का ठौर नहीं, वो बेघर है। जिसके पास मकान नहीं है, लेकिन

जमीन है वो आवासहीन कहलाएगा।

इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक नौकझोंक होती रही। यूडीएच मंत्री ने कहा कि भूमिहीन परिवारों की संख्या चाही है तो कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाकर दे देंगे। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने यूडीएच मंत्री के जवाब के बीच दो मंत्रियों के खड़े होने पर तंज कसते हुए कहा कि यहां एडवोकेट की जरूरत नहीं होती।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि आप साल पूछिए। भाषण देने का अधिकार नहीं है। जुली ने कहा सच्चाई बता दी तो कह

रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। जुली ने कहा कि संसदीय कार्यमंत्री जल्दीबाजी कर गए। उन्होंने आवासहीन का सवाल पूछा था, सदस्य ने गलती कर दी कि होमलेस पॉलिसी पर पूछ लिया। इन्होंने आवासहीन समझ लिया बात एक ही है। सवाल इतना सा है कि जिनके पास मकान नहीं है मकान कब तक दोगे?

जवाब गतत आया इसलिए कहा कि 2022 में जब होमलेस पॉलिसी आ गई, तो उसका मापदंड पूछे थे। संसदीय कार्य मंत्री ने खुद को ज्यादा काबिल साबित करने के चक्कर में मंत्रीजी को और मरवा दिया।

‘आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा पोषाहार दे रहे, जिन्हें कुत्तें भी नहीं खाए’

जयपुर (विसं)। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक रमिला खड्डिया ने जनजाति मंत्री पर आरोप लगाते हुए तंज कसे। मां बाड़ी कैटरीं पर 4-4 महीने से पोषाहार नहीं आ रहा। जो पोषाहार आ रहा है, जो एक रुपए के बिरिकट का पैकेट आ रहा है, उसको कुत्ते भी नहीं खा रहे हैं। ऐसा पोषाहार पहुंच रहा है, जो कुत्ते भी नहीं खाए, आप चेक करो। आप मंत्री हो, चेक क्यों नहीं करते हैं। इस पर टीएडी मंत्री ने कहा कि आपकी अध्यक्षता में ही कमेटी बना देता हूं।

■ कांग्रेस विधायक रमिला खड्डिया ने सदन में पोषाहार पर टिप्पणी की

इससे पहले उन्होंने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में टीएसपी के लोग लगाने चाहिए, लेकिन आपने जनरल को लगा दिया। मंत्री ने अपने रिश्तेदारों के कहने पर टीएसपी क्षेत्र में नौकरी लगा दी। गत 3-4 महीने से शिक्षकों को पेंमेंट नहीं मिल रहा है। मंत्रीजी, चेक करके देखो।

बूंदी जिले की कानून व्यवस्था पर हंगामा

जयपुर (विसं)। बूंदी जिले में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं और चरमपंती कानून व्यवस्था को लेकर बुधवार को विधानसभा में तीखा हंगामा देखने को मिला।

विधायक हरिमोहन शर्मा ने नियम-50 के अंतर्गत स्थान प्रस्ताव रखकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कठमरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बूंदी जिले में अपराधियों के हाईसेल इतने बुरेद हो चुके हैं कि हत्या, अपहरण और लूट जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं, जबकि पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है।

भील प्रदेश के लिए सड़क से सदन तक लड़ेंगे : कटारा

जयपुर (विसं)। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान चौरासी से भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) विधायक अनिल कटारा ने राज्य सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए भील प्रदेश की मांग उठाई। कटारा ने कहा कि आदिवासियों के जंगल उजाड़े जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं और पहाड़ों को काटा जा रहा है। आरक्षण के अनुरूप भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। अगर इसी तरह आदिवासी समाज की तौहीन

■ चौरासी के बीएपी विधायक कटारा ने आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया

होती रही, आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही तो हमारे पास अंतिम विकल्प यही है कि हम भील प्रदेश की मांग करते हैं। भील प्रदेश के लिए हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे और भील प्रदेश को लेकर रहेंगे।

‘धौराला में रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन कार्य अग्रिम चरण में है’

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के धौराला राज्यस् गांव में रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन का काम अग्रिम चरण में है। कर्नल राठौड़ प्रश्नकाल में विधायक मोतीलाल मीना के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ

■ उद्योग मंत्री ने कर्नल राठौड़ सदन में बताया कि “राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ उपयुक्त जमीनों को चिह्नित कर लैंड बैंक भी तैयार कर रही है, ताकि भविष्य में उद्योगों की मांग के अनुरूप उन्हें समय पर भूमि उपलब्ध कराई जा सके।”

उपयुक्त जमीनों को चिह्नित कर लैंड बैंक भी तैयार कर रही है, ताकि उद्योगों की मांग के अनुरूप उन्हें समय पर भूमि उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि लक्ष्मणगढ़ में उपलब्ध भूमि

उपलब्ध हैं, इनमें 110 प्लॉट आवंटित तथा 4 रिक्त हैं। इस क्षेत्र में कुल 40 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 2.5 एकड़ उद्योगों तथा शेष भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित है। उन्होंने बताया कि राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में डोलोमाइट प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग स्थापित हैं। खनन प्रतिबंधों के कारण इन उद्योगों की गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों को देखते हुए राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है।

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए राज्यस् गांव धौराला में 27.68 हैक्टेयर भूमि व लक्ष्मणगढ़ उपखंड के ग्राम मुण्डोजोई में 27.37 हैक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। धौराला राज्यस् गांव की चिह्नित भूमि आवंटन के लिए जिला कलक्टर व राज्यस् विभाग को समय-समय पर लिखा गया है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मणगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र का काम चिह्नित भूमि के आवंटन के बाद शुरू किया जायेगा।

पिछले दो साल से बीएसआर क्यों नहीं बदली? : हाईकोर्ट

जयपुर। राज्यस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण कार्यों की दूरें तय करने वाली बीएसआर (बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स) को पिछले दो साल से नहीं बदलने व नए टेंडर्स से प्राइस वेरिफेशन क्लॉज हटाए जाने को गंभीर माना है। साथ ही राज्य सरकार से पूछा है कि बीएसआर को क्यों नहीं बदला गया। यह भी पूछा है कि मौजूदा बाजार दरों की तुलना में पुराने बीएसआर को लागू रखने का क्या औचित्य है और क्या नियमों के तहत विभाग से अनुमति लेकर टेंडरों की शर्तों में बदलाव किया। इतना ही नहीं जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 जैसी बड़ी योजनाओं के लिए भी टेंडर जारी करते हुए प्राइस वेरिफेशन क्लॉज को पूरी तरह से हटा दिया गया। प्राथी की ओर

से आरोप लगाया कि कई नए टेंडरों में प्राइस वेरिफेशन क्लॉज को पूरी तरह से हटाया है। जबकि नियमानुसार हर साल बीएसआर का पुनरीक्षण जरूरी है ताकि बाजार में श्रम और सामग्री की वास्तविक दरों को प्रतिबिंबित किया जा सके। लेकिन साल 2023-24 के बाद प्रदेश में नया बीएसआर जारी नहीं किया, जबकि बाजार दरों में गिरावट हुई है। यह न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि इससे राज्यस् का भी नुकसान हो रहा है। प्राइस वेरिफेशन क्लॉज हटाकर ठेकेदारों को अनुचित लाभ व राज्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह राजस्थान पब्लिक वर्क्स फाइनैस एंड अकाउंट्स रूल्स और राज्य की घोषित नीति के विपरीत है।

‘पेपरलीक में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दो मंत्री जेल में होने चाहिए थे’

जयपुर (विसं)। राज्यपाल के अभिभाषण पर सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा के आरोपों पर सदन में माहौल गर्मा गया। गोपाल शर्मा ने पेपरलीक का मामला उठाते हुए कहा कि, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब पुलिस महानिदेशक ने पेपर लीक की फाइल देखी थी तो उन्होंने कहा था कि ईमानदारी से कार्रवाई की जाए तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दो मंत्री, जो उस समय राज्य मंत्री थे, उन्हें जेल में होना चाहिए था। गोपाल शर्मा ने कहा कि यह सब जानते हैं कि वह कौन मंत्री थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर यह लोग जेल में नहीं होंगे तो राजस्थान में कभी भी सुख-शांति का शासन नहीं आएगा, इसलिए इन दोनों को खुद ही आत्म समर्पण करना चाहिए।

सिविल लाइंस विधायक ने आगे कहा कि, कांग्रेस राज में एक पूर्व मंत्री तो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बताकर विदेश यात्रा तक पर ले गए थे। शांति धारीवाल सहित वरिष्ठ नेताओं को पता है वो पूर्व मंत्री कौन थे? गोपाल शर्मा के इन आरोपों के बाद सदन में माहौल गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने आपत्ति करते हुए कहा कि जो सदन का सदस्य नहीं है, उस पर चर्चा नहीं कर सकते। इस पर सभापति

■ सिविल लाइंस विधायक ने कहा कि सदन में “जब पुलिस महानिदेशक ने पेपरलीक की फाइल देखी थी, तब उन्होंने कहा था कि ईमानदारी से कार्रवाई की जाए तो पूर्ववर्ती सरकार के दो मंत्री जेल में होने चाहिए।”

संदीप शर्मा ने कहा कि अगर किसी का नाम लिया है तो उसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। इसके बाद भी विधायक शर्मा नहीं रुके, उन्होंने कहा कि “मैं जेल सुधार कमेटी का सदस्य हूं, जब मैं जेल में लोगों से मिलने गया तो वहां पर पेपर लीक मामले में बंद लोगों की बातें और उनका दर्द सुना। यह केवल पेपर लीक का मामला नहीं है यह पेपर के बाद पद पर नियुक्ति का मामला है। मैंने कुछ बहनों से पूछा कि क्या अपराध है, वे बोली नेता उन्हें ले गए और कहा कि वह व्यक्ति परीक्षा नहीं देगा, उसकी जगह पर आप लोग परीक्षा देंगे। हमारी बचियों को दूसरे की जगह परीक्षा दिलाने पर मजबूर करने वालों ने उनका जीवन का गला घोट दिया ।

यूनेस्को की हैरिटेज सूची में शामिल गुलाबी नगरी की विरासतों का संरक्षण किया जाए : वी. श्रीनिवास

मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक लेकर यूनेस्को के दिशा-निर्देशों पर चर्चा की

जयपुर (कासं)। यूनेस्को की विश्वविरासत सूची में शामिल “गुलाबी नगरी” (जयपुर) में हैरिटेज विरासतों के संरक्षण को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूनेस्को

■ मुख्य सचिव ने वॉल्ड सिटी जयपुर के लिए तैयार किए जा रहे “स्पेशल एरिया हैरिटेज प्लान” की प्रगति भी जानी

■ उन्होंने जयपुर परकोटे में स्वच्छता बनाए रखने, शहर के सौंदर्य को प्रभावित करने वाले बैनर, विज्ञापन व अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए

के दिशा-निर्देशों के मुताबिक पिंकसिटी का संरक्षण और पुरस्कृष्ट किया जाए। उन्होंने यूनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज सिटी स्टेटस के तहत आवश्यक कार्यों की समीक्षा करते हुए ‘होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच’ अपनाने पर जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग की संयुक्त टीम को पिंकसिटी का निरीक्षण कर कार्ययोजना को अंतिम



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उच्चस्तरीय बैठक में जयपुर परकोटे के संरक्षण पर चर्चा की।

रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने वॉल्ड सिटी क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने, शहर के सौंदर्य को प्रभावित करने वाले बैनर, विज्ञापन एवं अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से हैरिटेज गेट्स एवं प्रमुख मार्गों पर नियमित निगरानी रखते हुए अवैध तत्वों को हटाना जाए।

मुख्य सचिव ने वॉल्ड सिटी जयपुर के लिए तैयार की जा रही विशेष क्षेत्र विरासत योजना (स्पेशल एरिया हैरिटेज प्लान) की प्रगति की समीक्षा की। इसमें बताया गया कि बेस मैप, सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल,

आजीविका, पर्यटन, परिवहन एवं गतिशीलता, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण एवं परिरक्ष्य तथा विभागों एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित विभिन्न घटकों पर कार्य प्रगति पर है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग डॉ. देबाशीष गूरी, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन सहित पर्यटन, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास, नगर निगम जयपुर व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

तेज रफ्तार कार ने साइकिल पर जा रहे तीन मजदूरों को कुचला

जयपुर। राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार कार से दुर्घटना होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि पुलिस हादसों को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। इसके बावजूद भी आए दिन दुर्घटना होती नजर आ रही है। मंगलवार-बुधवार को मध्यरात्रि तेज रफ्तार कार ने विवाधर नगर थाना इलाके में साइकिल से घर जा रहे तीन मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया व दूसरे मजदूर ने उपचार दौरान दम तोड़ दिया।

थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि मंगलवार- बुधवार की मध्यरात्रि क्रॉस मॉल के पास चारों मजदूर मैरिज गार्डन से कैटरिंग का काम करने के बाद अलग-अलग साइकिल से जालपुर स्थित अपने किराए के मकान पर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने तीनों मजदूरों को जोरदार टक्कर मारते हुए फरार हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद विवाधर नगर पुलिस व भट्ठा बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए कोवटिया अस्पताल भिजवाया। वहीं चिकित्सकों ने देवत बेहरा उर्फ टट्पू (45) बालेश्वर ,ओडिशा निवासी को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल

बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव 7 फरवरी तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे

विधायक फंड के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। ईडी मामले की विशेष कोर्ट ने बुधवार को एमएलए फंड के दुरुपयोग के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बहरोड़ के पूर्व एमएलए बलजीत यादव को 7 फरवरी तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने यादव को कोर्ट में पेश कर कहा कि उसने फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपए का फंड हड़पा है। उससे अभी इस मामले में पूछताछ करनी है, इसलिए उसे रिमांड पर दिया जाए। यादव के वकीलों ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर यादव को तीन दिन के रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में पूर्व विधायक यादव पर एमएलए फंड से 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि के दुरुपयोग व गबन का आरोप है। जिस पर ही ईडी ने पीएमएलए के तहत यादव के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ईडी ने अलवर के शाहजहाँपुर टोल प्लाजा से मंगलवार रात पूर्व विधायक बलजीत यादव को हिरासत में लिया था। बाद में पूछताछ के लिए जयपुर स्थित ईडी ऑफिस लाया गया। पूछताछ के बाद बलजीत यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।

कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने पहले 6 दिन व बाद में 4 दिन के लिए यादव को रिमांड पर देने का आग्रह किया। ईडी का आरोप है कि पूर्व एमएलए यादव के निर्देश पर परिचित व रिश्तेदारों की 4 फर्मों को खेल सामग्री खरीद के टेंडर मंजूर हुए, जिसमें बाजार मूल्यों की तुलना में कई गुना कीमत पर सामान की खरीद कर फर्जीबाड़ा किया। ईडी के अधिवक्ता अजातशत्रु मीना ने कहा कि सरकारी स्कूलों में खेल सामान की आपूर्ति करने वाली सभी चारों फर्म पूर्व विधायक बलजीत यादव के कर्मचारी व रिश्तेदारों की है।

■ इस मामले में यादव पर एमएलए फंड से 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि के दुरुपयोग व गबन का आरोप है

टेंडर में की गई आपूर्ति का भुगतान होने के बाद ये सभी फर्म बंद हो गईं। खेल सामग्री की आपूर्ति से प्राप्त दो करोड़ 74 लाख 75 हजार रुपए का उपयोग वैशाली नगर में प्लॉट खरीदने, बहरोड़ के पास 12.50 बीघा कृषि भूमि की खरीद के लिए अग्रिम देने व चुनौती रैली में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने में हुआ है।

यादव के अधिवक्ता ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तारी की, जबकि एसीबी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का स्टैंड है। यह राजनीति प्रेरित व राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र का मामला है। अभी तक 5 बार जांच हो चुकी है, जिसमें किसी को दोषी नहीं माना गया। पेशी के दौरान बलजीत यादव ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक साक्षिण के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहरोड़ के मौजूदा भाजपा विधायक जसवंत यादव अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं और इसी कारण उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जसवंत यादव गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

सार-समाचार



‘पेरेंटिंग सिस्ट्रेंस फ़ॉर रेज़िंग रॉकस्टार्स’ का विमोचन बुधवार को एमजीडी गर्ल्स स्कूल जयपुर में किया गया।

जयपुर। पालन-पोषण को केवल नियमों या अपेक्षाओं तक सीमित न रखते हुए उसे संवेदनशील संवाद, धैर्य और समझ की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती पुस्तक ‘पेरेंटिंग सिस्ट्रेंस फ़ॉर रेज़िंग रॉकस्टार्स’ का विमोचन बुधवार को एमजीडी गर्ल्स स्कूल, जयपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। 2-पेजेज बुक क्लब, जयपुर द्वारा आयोजित इस ओपन-फॉर-ऑल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और पुस्तक प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के संबोधन से हुई जिसमें वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपक शिवपुरी, एमजीडी गर्ल्स स्कूल की निदेशक अर्चना एस. मनकोटिया, डॉ. एस. सीतारामन, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ ने अपने संबोधन में ‘सुनने की कला’ की प्रभावी पालन-पोषण का मूल बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों की बात बिना जल्दबाजी और निर्णय के सुनना, उनके आत्मविश्वास को मजबूत करता है और रिश्तों को गहराई देता है। साथ ही आज के तेज और शोरभरे जीवन में मानसिक शांति बनाए रखने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शांत मन ही सही निर्णयों की नींव होता है और बच्चों को सबसे पहले वही वातावरण घर से मिलता है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. मयंक गुप्ता और रिधिमा चौधरी के साथ एक संवादात्मक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसका संचालन 2-पेजेज बुक क्लब के सदस्य और युवा अभिभावक प्रणिता एवं अंकिता डागा ने किया। इस दौरान किताब से जुड़े पहलुओं पर बात हुई, जिसमें पुस्तक के सह-लेखक और मनोचिकित्सक डॉ. मयंक गुप्ता ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्रतिभा से अधिक प्रयास जीवन में स्थायी सफलता दिलाता है। बच्चों में मेहनत करने की आदत विकसित करना, उन्हें किसी भी कौशल से अधिक सशक्त बनाता है मनोवैज्ञानिक रिधिमा चौधरी ने कहा कि जब बच्चे को समझा जाता है, तब वह खुद को समझना सीखता है। चर्चा में अभिभावकों के वास्तविक सवालों, दैनिक चुनौतियों और व्यावहारिक समाधानों पर खुलकर बातचीत हुई। इस अवसर पर 2-पेजेज बुक क्लब के संस्थापक सदस्य डॉ. राम गुलाटी, प्रमया रामजेवाल और मोहित बत्रा भी उपस्थित रहे।

मातृ वंदना की रैकिंग में राजस्थान प्रथम

जयपुर (कासं)। उपमुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमार ने आईसीडीएस राजस्थान को एक बार फिर से प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में राष्ट्रीय स्तर पर जारी मासिक रैंकिंग, (जनवरी 2026) में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी है। दिया कुमार ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आईसीडीएस की ओर से सितम्बर 2025 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान करने के पश्चात पुनः जनवरी 2026 में भी प्रथम स्थान प्राप्त करना गर्व की बात है। इसके लिए विभागियों अधिकारियों द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा निरंतर कीर्तिमान रचे जा रहे हैं, जिसमें उक्त उपलब्धियों के साथ ही पिछले वर्ष 2025 में विभाग को पोषण माह में दूसरा तथा पोषण पखवाड़ा में प्रथम स्थान मिलना भी उल्लेखनीय उपलब्धि है। आईसीडीएस निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि राजस्थान के प्रथम स्थान के साथ ही इस मासिक रैंकिंग में कर्नाटक दूसरे स्थान पर तथा असम तीसरे स्थान पर है वहीं महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर है।

बंधन बैंक ने मासिक एवरेज बैलेंस घटाया

जयपुर। बंधन बैंक ने स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट के लिए मासिक औसत शेष (एएमबी) की आवश्यकता में महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है, जबकि खाते की सभी सुविधाएँ और लाभ पहले की तरह ही रहेंगे। स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट के लिए एएमबी की आवश्यकता को 5000 रुपए से घटाकर 2000 रुपए किया जा रहा है। 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होगी। बंधन बैंक निदेशक एवं मुख्य व्यवसाय अधिकारी राजेंद्र कुमार बक्वर ने कहा, गणतंत्र दिवस समानता और सशक्तिकरण का उत्सव है। हालांकि, इस खाते से जुड़े प्रोडक्ट फीचर्स और लाभों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह कदम देशभर के लाखों ग्राहकों, विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बैंकिंग को अधिक किफायती और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता कम कर, बंधन बैंक ने यह सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी वित्तीय दबाव के पूर्ण-सेवा बचत खाते के लाभ उठा सके।

‘एसीबी एसआईटी के मुखिया पेश हों’

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटालों की प्रभावों जांच नहीं करने से जुड़े मामले में एसीबी की ओर से गठित एसआईटी के मुखिया को 5 फरवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ में आदेश टीएन शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुचावाई के दौरान एडिशनल एसपी श्याम सुंदर और उपाधीक्षक सुरेंद्र पंचोली अदालत में हाजिर हुए उनकी ओर से जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पीसी भंडारी ने कहा कि 6 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पिछले 5 साल के टेंडर की जांच की आदेश दिए थे और याचिकाकर्ता को कहा था कि वह चाहे तो इस संबंध में अपना अभ्यावेदन एसीबी को दे सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से 27 मार्च 2015 में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दस्तावेजों के साथ एसीबी ने अभ्यावेदन पेश किया। इसके बावजूद भी एसीबी ने केवल एक मामले में एफआईआर दर्ज की और उसमें भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया।



Celebrating Positivity, One Smile at a Time

Are you a glass-half-full or glass-half-empty person? If you're a natural optimist in life, you might consider yourself a glass-half-full. Others might feel challenging to be positive. Optimist Day, first celebrated in 2019 in Croatia, is the perfect excuse to embrace positivity, whether you're a natural optimist or a bit more sceptical. The festival, created by Somersby Cider, brought people together in Zagreb to enjoy summer sunshine, bright yellow balloons, and cheerful toasts with fellow dreamers. It's a day to focus on the good, celebrate life's small joys, and inject a little fun-fuelled optimism into everyday life. Optimist Day reminds us that positivity is contagious and worth celebrating.



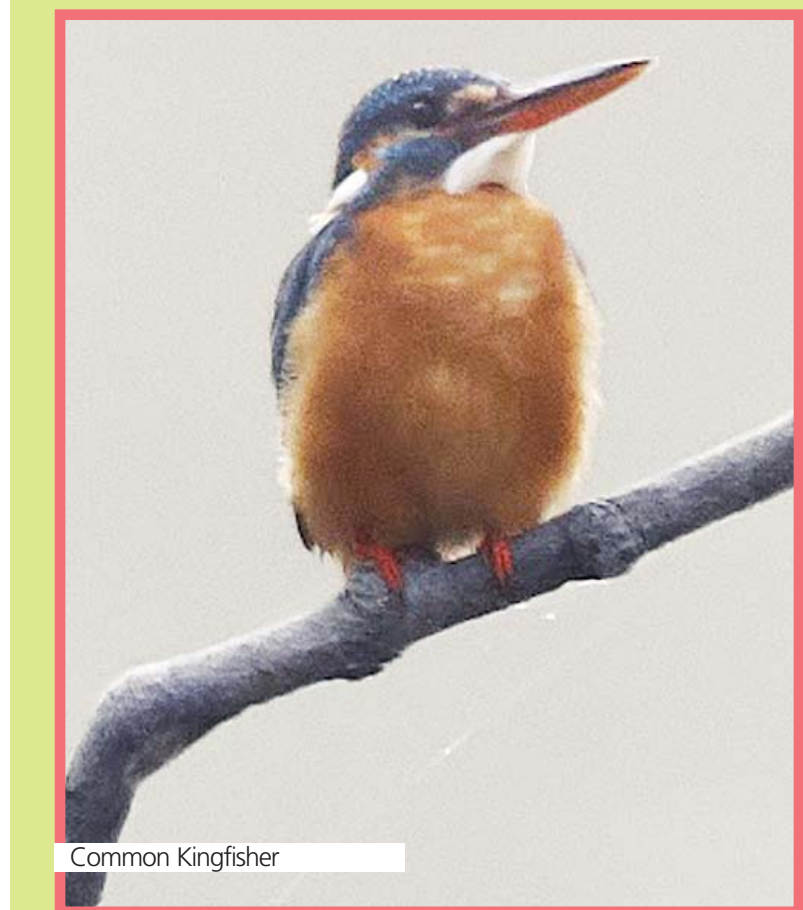
Grey Jungle Fowl Rooster

Coming Home To The Bulbul, the Crow Pheasant, and the scream of the Peacock

PART:2



Red-naped or Indian Black Ibis

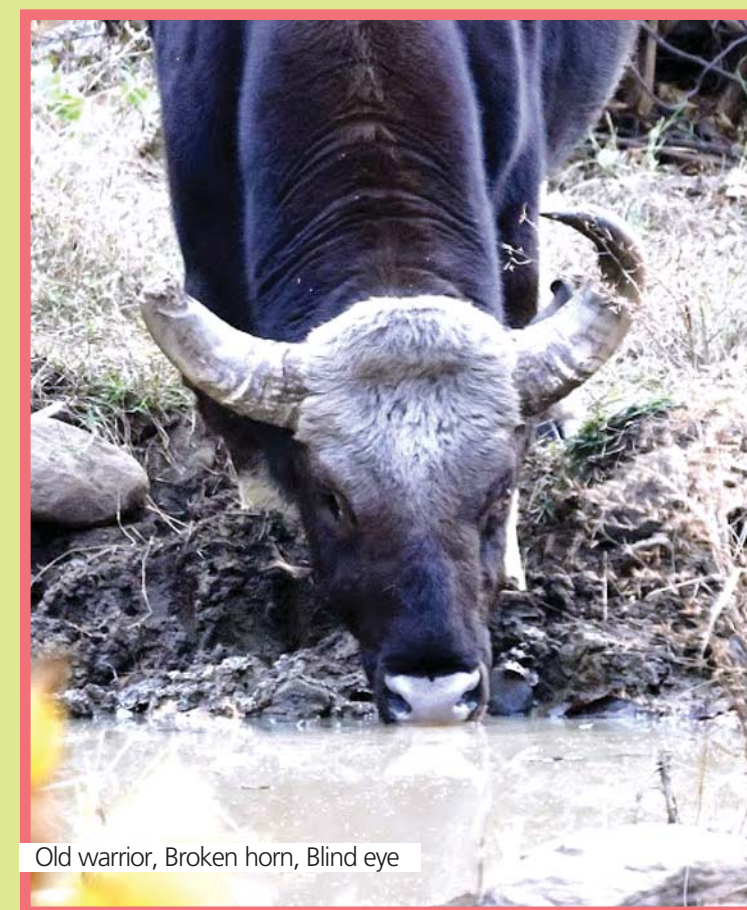


Common Kingfisher

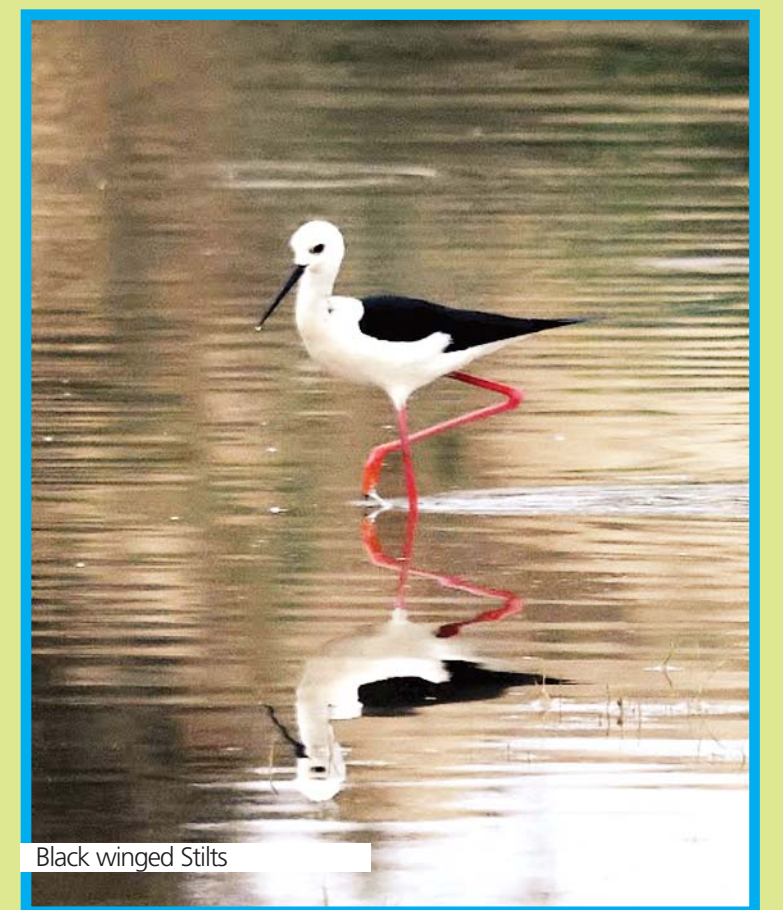


Tiger, 2 year-old scratchy nose

Incidentally, this is why I am against trophy hunting where the best of the species gets killed, for no reason other than that it is so magnificent. This takes the best genes out of the breeding pool, reducing the quality of the species over time. We have seen this happen with animal after animal, all victims to mankind's insatiable egos. Another record mentions a cast antler from the Khandesh district measuring 52 inches, on the main beam. Chital antlers are slender and also three pointed and sweep backwards over the shoulders and curve upwards. The record for Chital antlers is 41 inches. Chital are among the most beautiful deer in the world and have been exported all over the world and you can see them in parks in America and Europe and elsewhere.



Old warrior, Broken horn, Blind eye



Black winged Stilts



Mirza Yawar Baig
Naturalist and Wildlife Conservationist

Sambar shed their antlers primarily in March and April, while Chital shed theirs between March and July. That is how we were able to see two magnificent Sambar and Chital stags with their racks intact. Sambar are the largest deer in India. Only males have antlers that typically feature three tines (points) on each beam. Sambar antlers are large,

rugged, and can reach lengths of up to 110 cm (43 inches). The record for Sambar antlers in India is an animal that was shot in Bhopal which had antlers with a main beam of 50.5 inches. Incidentally, this is why I am against trophy hunting where the best of the species gets killed, for no reason other than that it is so magnificent. This takes the best genes out of the breeding pool, reducing the quality of the species over time. We have seen this happen with animal after animal, all victims to mankind's insatiable egos. Another record mentions a cast antler from the Khandesh district measuring 52 inches, on the main beam. Chital antlers are slender and also three pointed and sweep backwards over the shoulders and curve upwards. The record for Chital antlers is 41 inches. Chital are among the most beautiful deer in the world and have



Great Egret and two Black winged Stilts

been exported all over the world and you can see them in parks in America and Europe and elsewhere.

Both Sambar and Chital are on the menu for tigers and leopards and are well aware of this status and so are very skittish in forests where there are tigers and leopards. That makes them the most reliable informers about the movements of these two apex predators. Especially Sambar because Chital sometimes tend to get too high-strung and nervous and will sound their high-pitched bark even at shadows. But Sambar will not call until they can see the tiger or leopard and so their deep 'belling' is a totally reliable signal that the tiger is on the move and has been seen. The jungle talks to those who understand its language.

The Langur sentinel, from his perch on the highest tree, calls first, then Chital and finally Sambar and

we head in that direction.

As we round a bend, we see, off to the right, a tiger on a low tree. He climbed up there for reasons he refused to disclose, but when he heard our Gypsy, he jumped down and started for the road. It was a two-year-old male cub who, our guide informed us, had got separated from his mother and two other siblings. Not too alarming a situation but one which he needs to correct soon. Tiger cubs are totally dependent on their mother for protection from other tigers, leopards, hyenas, wolves and almost anything else, all of whom firmly believe that the only good tiger is a dead tiger. And that the best thing about a cub is how easy it is to kill. Full grown Bengal tigers stand 3.5 feet at the shoulder, measure 10-11 feet from the tip of the nose to the tip of the tail and weigh between 180-280 kilograms of liquid steel, otherwise called muscle.

Some big specimens can go up to 300 kilograms. Not easy to kill, to say the least. But cubs are vulnerable and need constant protection. Tiger cubs also need their mother to teach them everything to do with jungle lore and how to hunt. For up to and sometimes more than two years, they can't hunt for themselves and their mother hunts and brings the kill to them or calls them to the kill depending on how big they are. That is another reason why hunting tigers is such an evil thing, because if you shoot the mother and she has cubs, you have effectively wiped out the entire family.

We moved forward slowly to keep the dust down. The cub came



into the road and walked along it, following us. If we waited too long and he got close, he would veer off into the undergrowth by the roadside. We would hurry forward, and he would come back into the road. The problem with moving and stopping was the dust, which was so heavy that every time we stopped, I couldn't see the tiger, thanks to the cloud of red dust that would cover him and us. We had several minutes of this follow the leader game when the tiger came to a signal tree. There, he reared up on his hind legs and hugged the tree, smelled the calling cards of other tigers who had been in the area, rubbed his face against the bark of the tree to leave his scent, and then, scored it



Tiger Umred.



Black winged Stilts

#HOME



Sparring Gaur bulls

with his razor-sharp claws. Mature tigers also spray urine on signal trees to mark their territory and demonstrate dominance.

Eventually, the tiger wandered off into the jungle. We proceeded onwards and took a long detour along the boundary of the fields belonging to a village adjacent to the park. In that open area to my great delight, I spotted a Chinkara (Gazella bennettii), the Indian gazelle. It is a small, graceful antelope native to South Asia's arid plains, deserts, and dry forests, known for its speed, shy nature, and ability to survive without much water. It has a reddish-buff coat, distinctive black and white facial stripes, and lives alone or in very small family groups. I was thrilled to see the Chinkara, which is so shy and elusive, that it is a very difficult animal to spot.

We came upon a small family herd of Gaur (Indian bison, Bos

gaurus), grazing in a forest clearing. One of the big cubs was chewing on a Chital bone, remnants of a tiger kill. They do this when they feel the need for a calcium supplement. Two young bulls were sparring, not a serious fight, but the needle-sharp points of the horns can still do damage. At a small water seepage, along came an old bull. A veteran warrior with one horn tip broken off and blind in the right eye. As he lowered his head to drink, he was joined by a Blue Bull male and they drank in companionable silence. A Grey Mongoose, one of a pair, watched us in open curiosity, torn between his need to discover who we were and following his mate who decided to leave him behind and disappeared in the bush.

As the day drew to a close, we came upon another clearing, literally teaming with Grey Jungle Fowl roosters. Just one or two hens, but

some marvelous, flamboyant roosters. Eventually and reluctantly, we headed back to the gate, bodies pleasantly sore with being banged around in the Gypsies, driven over atrocious roads by drivers who could easily win the Dakkar Rally and do their best to prove that to you every day.

I was returning to the Indian jungle after almost eight years of having been away in America and elsewhere. For me, it was coming home. The calls of the Red-vented Bulbul, the Crow Pheasant, the Rufus Treepie, the Did-you-do-it of the Red-wattled Lapwing, the Kok-kow-Kow-Kok of the Grey Jungle fowl and the scream of the Peacock, signaling the coming of nightfall, were all music to my ears. Music long unheard and yearned for.

We stopped for tea beside a lake and I spotted a Great Egret, Black-

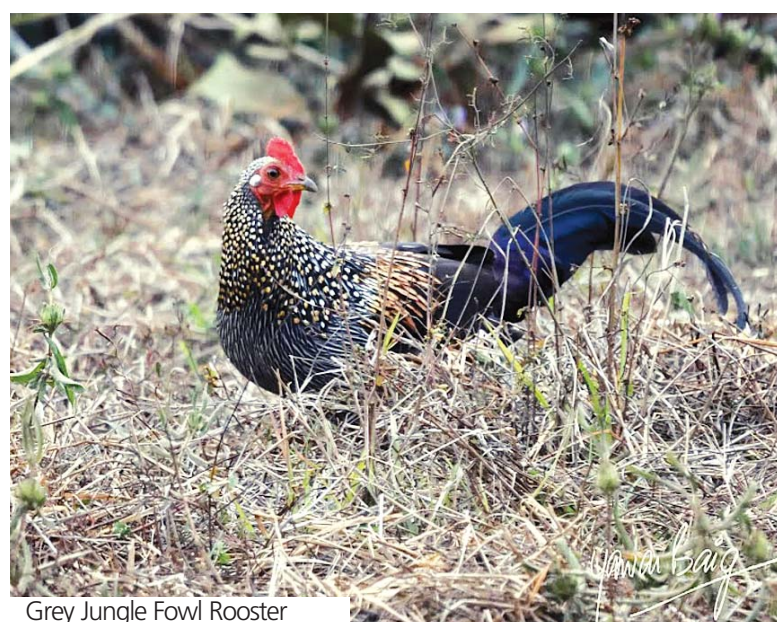
winged Stilts, Little Egret, Common Kingfisher and Pied Kingfisher and an Asian Open-billed Stork, standing off to one side, refusing to socialize with common folk.

Later in the night, after a very welcome shower to wash off half the earth that was sticking to me, as I sat outside my room at the resort, I heard the hoot of Spotted Owlets, the call of the Nightjar which sits in the middle of pathways lying in wait for flying insects. He comes off his perch on the ground like a rocket of doom for the insect, catching it in mid-flight and comes back to his seat on the ground. Finally, as I was about to retire, I heard the bark of the Chital, signaling that the tiger was on the move. His day begins when mine ends.

Concluded.
rajeshsharma1049@gmail.com

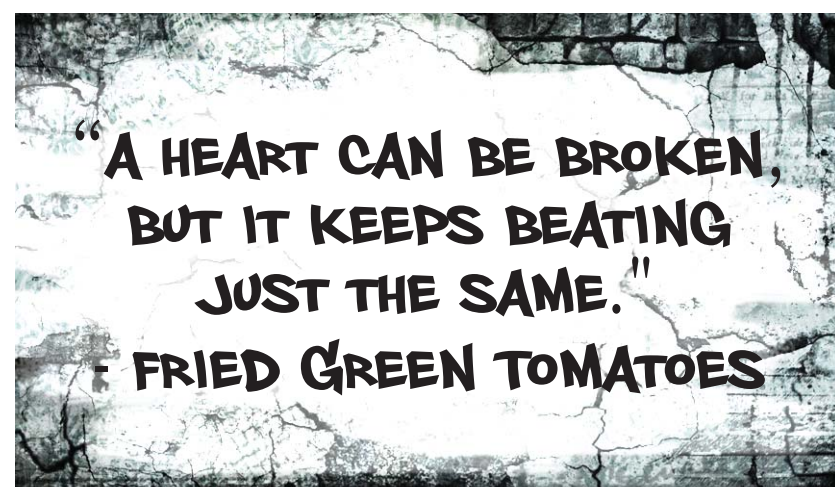


Sparring Gaur bulls, friendly fight

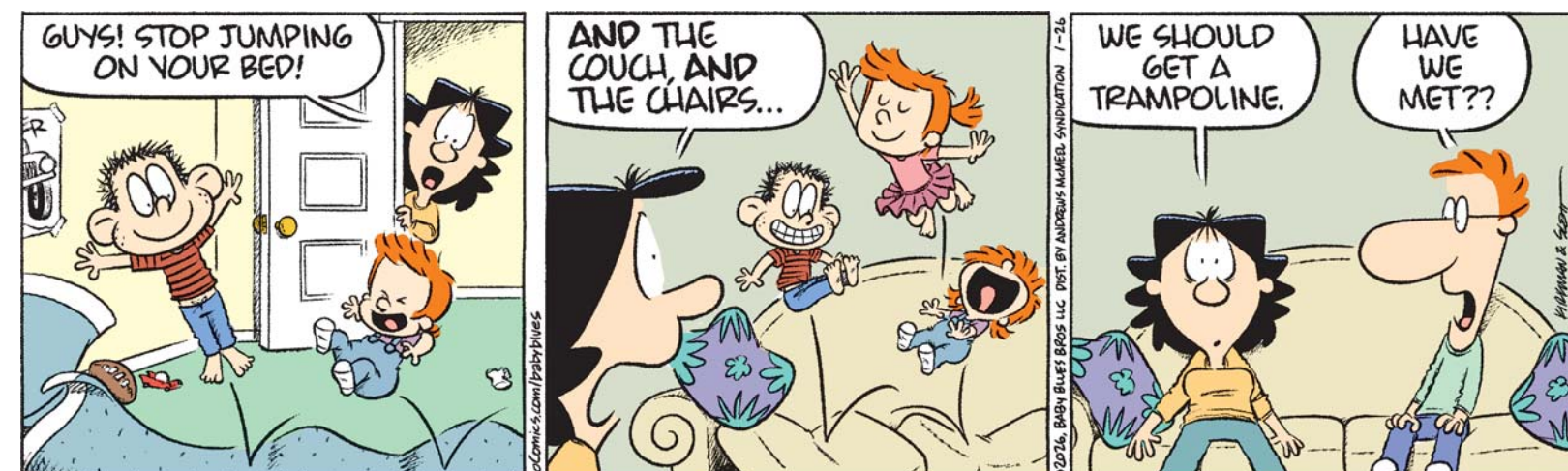


Grey Jungle Fowl Rooster

THE WALL

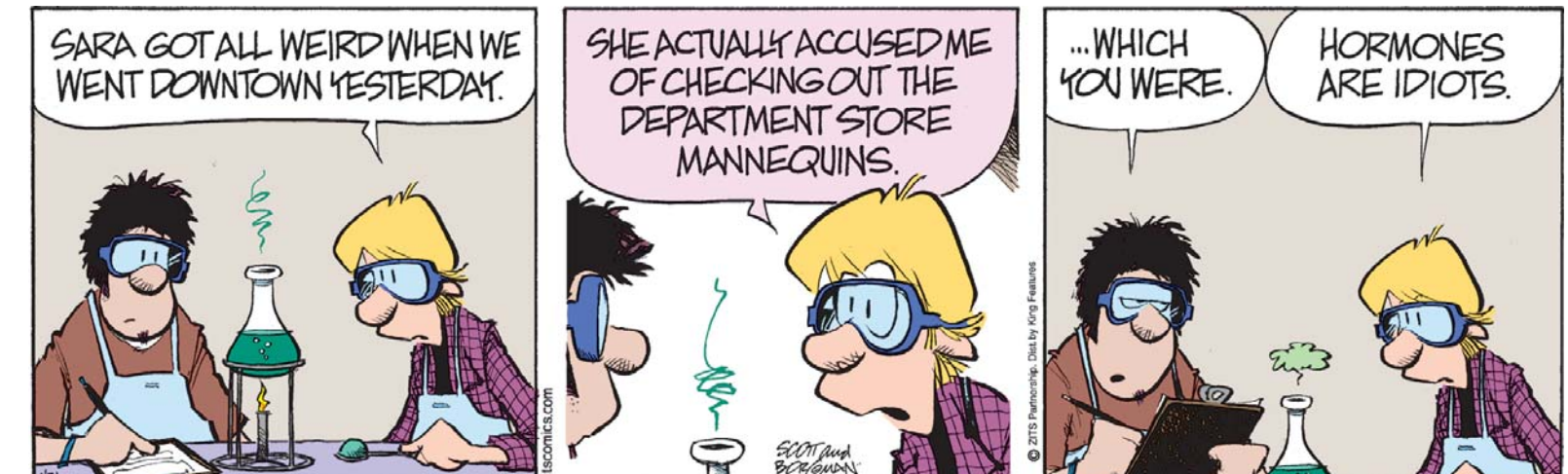


BABY BLUES



By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman

संक्षिप्त

बजट क्वेस्ट 2026 के पोस्टर का विमोचन

अलवर (निसं)। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिकाल शुक्ला ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माय भारत पोर्टल पर बजट क्वेस्ट 2026 कार्यक्रम के पोस्टर विमोचन किया।जिला कलक्टर ने बताया कि युवा कार्यक्रम मंत्रालय की ओर से यह राष्ट्रव्यापी युवा-केंद्रित पहल देश के युवाओं में केंद्रीय बजट की समझ को बढ़ाने, बजटीय प्रावधानों को अधिक सुलभ,प्रासंगिक और नागरिक-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत वि्वज एवं निबंध राउंड के बाद क्वालीफाई होने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद करने का अवसर प्राप्त होगा। माय भारत केंद्र के जिला युवा अधिकारी श्री रंजक यादव ने बताया कि माय भारत पोर्टल पर आयोजित होने वाला यह इनोवेटिव कार्यक्रम बजट झ्र 2026 के संबंध में आम नागरिकों को जागरूक करने की पहल है। बजट क्विज 2026 प्रश्नोत्तरी के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए युवाओं को पोर्टल अथवा माय भारत ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा।

दुकान में देर रात नकदी व डेयरी के लाखों के उपकरण चोरी

पावटा। आतेला-बजरंगपुर रोड पर केरली गांव में देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ता हवा सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि केरली निवासी फूलचंद गुर्जर की गोपाल जनरल स्टोर एवं लोटस डेयरी उत्पाद की दुकान पर रात करीब 1 बजे के बाद अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोर दुकान से नकदी व अन्य लाखों का सामान व उपकरण लेकर फरार हो गए। सुबह जब दुकान मालिक फूलचंद गुर्जर दुकान पर पहुंचे तो चोरी का पता चला, जिसके बाद क्षेत्र में ससन्नी फैल गई। घटना की सूचना भाबर थाना पुलिस को दी गई। ग्रामीणों ने पुलिस से चोरी की घटना का जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।

मांजूकोट में 55 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन

पावटा। उपखंड एवं कुलपूतली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मांजूकोट में विधायक हंजराम पटेल ने 55 लाख रुपये की लागत से निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच मनोज कुमार वर्मा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में बीसीएमओ कृष्ण सिंह व जिला पादर भोमराम गुर्जर उपस्थित रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक पटेल ने कहा, यह उप स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्रवासियों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार, मां-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य जरूरी चिकित्सा सुविधाएं गांव में ही मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का गवां स्तर तक सुदृढ़ होना ही सच्चे विकास की पहचान है। इस दौरान भाजपा नेता गोपाल अग्रवाल, भूरी-भड़ाज सरपंच कैलाश चंद स्वामी, ड्राकिपुरा प्रशासक रोहित बायला, जिला पार्षद तेजपाल, हरिद्वारी लाल स्वामी, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कमल सैनी, डेलीगेट नरेंद्र गुर्जर, श्रीराम यादव समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, ग्रामीणजन एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

एडीएम ने नर्सिंग हॉम पर लगाया 5 हजार का जुर्माना

दौसा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद के प्रशासक अरविंद्र कुमार शर्मा ने बुधवार को दौसा शहर की सफाई व्यवस्थाओं को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खण्डेलवाल नर्सिंग होम के आसपास खुले में बेस्ट बायो मैडिकल पाये जाने पर नर्सिंग हॉम संचालक को जमकर लताड़ पिलाते हुये 5 हजार रुपये जुर्माना किया है, साथ ही भविष्य में इस प्रकार की गवबडी पाये जाने पर जुर्माना के साथ कठोर कार्रवाही की चेतावनी दी है। बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद के प्रशासन अरविन्द्र कुमार शर्मा, नगर परिषद आयुक्त कमलेश मोहन सिंह तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों ने दौसा शहर के विभिन्न वाडों में एवं बाजारी में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया।

5 करोड़ 95 लाख रुपये की डीएमएफटी से विकास कार्यों को स्वीकृति जारी



सांसद राव राजेंद्र सिंह व विधायक कुलदीप धनखड़ की अनुशंसा पर स्वीकृतियां जारी की गईं ।

लाडाकाबास पावटा में 20 लाख की लागत से दो कक्षा कक्ष मय बरामदा एवं शौचालय निर्माण कार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा पावटा में 15 लाख की लागत से दो कक्षा कक्ष मय बरामदा निर्माण कार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डाणी थालोड़ की में 18 लाख की लागत से दो कक्षा कक्ष मय

बरामदा निर्माण एवं छत मरम्मत कार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा में 10 लाख की लागत से महिला एवं पुरुष शौचालय निर्माण कार्य, आंगनवाड़ी केन्द्र ठीकरिया में 12 लाख की लागत से एक कक्ष मय बरामदा एवं स्टोर निर्माण कार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छानी की डाणी वीर

‘दौसा शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए नगर परिषद की नई पहल’

- नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार एवं नगर परिषद के प्रशासक के निर्देशन में नगर परिषद क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 5 फरवरी से शहर में वाई वाइज स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा**

दौसा(निसं)। नगर परिषद ने शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत वाईवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक वार्ड की सफाई के लिए एक-एक दिन विशेष तौर से तय किया गया है। इसकी शुरुआत 5 फरवरी से वार्ड संख्या एक से होगी।

नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार एवं नगर परिषद के प्रशासक अरविंद्र शर्मा के निर्देशन में प्रशासनिक दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए नगर परिषद क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 5 फरवरी से शहर में वाई वाइज स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसकेलिए सभी जमादारी को वाई वाइज सफाई करवाने की जिम्मेदारी दी गई है।

साथ ही 10-10 सफाई कर्मचारियों की प्रत्येक वार्ड की सफाई के लिए ड्यूटी लगाई गई है। पहले दिन वार्ड संख्या एक की सफाई के साथ इस अभियान की शुरुआत होगी।

आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि वार्ड के सफाई कार्य के दौरान वाईवासियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे दिन संबंधित वार्ड में सफाई कार्य किया जाएगा। इस

डीएमएफटी के माध्यम से मिलने वाले संसाधनों का उपयोग जनहित में किया जाएगा- राव राजेंद्र सिंह

तेजाजीनगर में 15 लाख की लागत से दो कक्षा कक्ष मय बरामदा निर्माण कार्य, राजकीय प्राथमिक विद्यालय दौल्यावाली वीर तेजाजीनगर पावटा में दो कक्षा कक्ष मय बरामदा निर्माण कार्य हेतु, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुरा पावटा में 20 लाख की लागत से डोम टीन सेड (6580) लगाने के कार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोली कोठी चतरपुरा में 15 लाख की लागत से दो कक्षा कक्ष मय बरामदा निर्माण कार्य, महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय खातोलाई में 15 लाख की लागत से दो कक्षा कक्ष मय बरामदा निर्माण कार्य, 15 लाख की लागत से पुस्तकालय भवन मय कम्प्यूटर एवं फर्नीचर निर्माण कैरोडी, 15 लाख की लागत से पुस्तकालय भवन मय कम्प्यूटर

तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

टोंक(निसं)। नव्या उपखण्ड के राजकीय क्विा कॉलेज दत्तवास में कार्यरत विद्या संबल सहायक आचार्यों ने नायब तहसीलदार छितरलाल मीना को ज्ञापन सौंपकर बताया कि उन्होंने पांच सत्रों की सेवा के बाद हटाए जाने का विरोध करते हुए रोजगार गारंटी और सेवा की सुनिश्चितता की मांग की है। सहायक आचार्यों ने ज्ञापन में बताया कि वे प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में पिछले पांच सत्रों से विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत हैं। अब सरकार उन्हें हटाकर पांच वर्ष के लिए अस्थायी सविदा भर्ती कर रही है, आचार्यों का कहना है कि उन्होंने अपने युवा जीवन के पांच साल निष्ठापूर्वक सेवा की है। उन्होंने यह भी बताया कि माननीय न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया है कि एक सविदा कार्मिक को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे सविदा स्थलों के बारे में जमादार को अवगत कराएं, ताकि हम सब मिलकर वाई को स्वच्छ बना सकें।

दौरान वाईवासियों के बताए अनुसार

स्थानों को भी साफ किया जाएगा।

उन्होंने वाईवासियों से आग्रह किया है कि वह नियत दिवस को अपने वार्ड की साफ-सफाई में सहयोग कर सामुदायिकता की भावना का परिचय दें और सफाई की जरूरत वाले विशेष स्थानों के बारे में जमादार को अवगत कराएं, ताकि हम सब मिलकर वाई को स्वच्छ बना सकें।

साईबर क्राईम, आपदा पीड़ित प्रबंधन के बारे में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

शाहपुरा(निसं)। दक्ष पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला जयपुर अध्यक्ष भंवरलाल गुगुलिया एवं तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा अध्यक्ष ललितला शर्मा अपर प्रजिला एवं सत्र सेशन न्यायाधीश प्रथम के निर्देशन में अधिकार मित्र दिनेश कुमार शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण एवं नालसा जाग्रति योजना के अंतर्गत साईबर क्राईम, नशा

- साईबर ठाणों के द्वारा डिजिटल अरेस्ट सिनियर सिटीजन के साथ, सरकारी सर्विसेज के बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी होने पर साईबर हेल्पलाइन नंबर 1093 पर सूचित करना है**

स्वयं को बचाये रखना है। इसके लिए स्वयं को अपनी शिक्षा को समय की मांग आधारित बनाने के लिए सतर्कता के साथ साईबर ठाणों के द्वारा डिजिटल अरेस्ट सिनियर सिटीजन के साथ, सरकारी सर्विसेज के बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी होने पर साईबर हेल्पलाइन नंबर 1093 पर सूचित करना है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने घरों में स्वयं के जन्मदिन पर एक फलदार " पौधा को नाम " अवश्य लगावे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना,बैंक में जन-धन खाते योजनाओं के अंतर्गत खाता खुलवाये। इस शिविर में विद्यालय के अध्यापक स्टाफ में श्रीधम यादव, राजेन्द्र श्योणन, फूलचंद स्वामी, मोहन लाल यादव इत्यादि उपस्थित रहे। लाभार्थियों की संख्या 146 रही।

गौवंश को तीन दिन बाद मृत बाहर निकाला

पावटा(निसं)। उपखंड क्षेत्र पावटा के ग्राम भांकारी में मानवात और गौ सेवा की मिसाल पेश करते हुए गौ रक्षकों ने तीन दिन से करीब 150 फीट गहरे कुएं में गिरे गौवंश को बाहर निकाला। लेकिन जब तक गौ वंश की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय गौ रक्षक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। जानकारी के अनुसार गौवंश अचानक फिसलकर गहरे कुएं में गिर गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन कुएं की अधिक गहराई और संकरी संरचना के कारण सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद गौ रक्षकों की सूचना दी गई। जिस पर बजरंग दल प्रखंड सयोजक पवन शर्मा पावटा, निवेश शर्मा, सुभाष सिंह राजनोला, सचिन सिंह, अजय सिंह, गुडु, दिनेश, करतार, जिपी सहित गौ रक्षक टीम ने रस्सियों और अन्य सुरक्षा उपकरणों की मदद से लगातार प्रयास किया कठिन परिश्रयतियों और जोरिम भरें हालात के बावजूद टीम ने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए गौवंश को बाहर निकाल लिया।

- आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने निदेशक से की मुलाकात,**
- वासुदेव मालावत से मुलाकात कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं की जानकारी देते हुए मानदेय में वृद्धि करने की मांग की**

के रूप में पाँच लाख रुपये के पैकेज की व्यवस्था करने का सुझाव रखा, ताकि सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें सम्मानजनक सुरक्षा मिल सके। चर्चा के बाद प्रतिनिधि मण्डल स्वास्थ्य विभाग पहुंचा, जहाँ उन्होंने आशा सहयोगिनियों की समस्याओं एवं उनके कार्यक्षेत्र से जुड़े मुद्दों को अधिकारियों के समक्ष रखा और उनके समाधान की मांग की।

गिरदावर सर्किल पर आज ग्राम उत्थान शिविर लगेगे

दौसा(निसं)। प्रगतिशील किसानों और पशुपालकों की सहभागिता सुनिश्चित कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए 5 फरवरी को दौसा सहित 11 गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविंद्र शर्मा ने बताया कि 5 फरवरी को दौसा, अरनिया, गुढा आशिकपुरा, घूमणा, गाजीपुर, बैजूपाड़ा, मण्डावरी, बड़ागांव, निजामपुरा, बनियाना एवं कुण्डल गिरदावर सर्किल पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 6 फरवरी को सूरजपुरा, देलाडी, बसवा, छोकरवाड़ा, खेड़ला बुजुर्ग, उकरूंद, बिलौना कर्ला, आलूदा, रजवास एवं काली पहाड़ी भू अभिलेख निरीक्षक मुख्यालय पर शिविर लगेगे।

राजसेस महाविद्यालयों में संविदा नियुक्तियों से बैक डोर एंट्री का खेल रोकने की मांग

- सोडाणी समिति की सिफारिशें सार्वजनिक कर लागू करने की मांग**
- अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की श्री राधा गोविंद महाविद्यालय इकाई पदाधिकारियों ने मंगलवार को काली पट्टी बांधकर तथा प्ले काइर्स पर अपनी मांगें प्रदर्शित कर कॉलेज के मुख्य द्वार पर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया**

कार्यकाल में सत्र 2023-24 एवं 2024-25 में 71 अतिरिक्त महाविद्यालयों को वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की मूल भावना के विपरित है। इन महाविद्यालयों में स्थायी अकादमिक ढांचे का अभाव, अपर्याप्त अधीसरचना एवं संसाधन, शोध एवं नवाचारी संभावनाओं का न होना तथा संविदा एवं अस्थायी नियुक्तियों पर आधारित अध्यापन व्यवस्था राज्य की उच्च शिक्षा को गुणवत्ता, बहुविषयकता एवं अकादमिक निरंतरता से दूर ले जा रही है। महासंघ ने अवगत कराया कि सत्र 2020-21 से 2022-23 के मध्य राजसेस योजना में 303 नवीन महाविद्यालय खोले गए तथा वर्तमान सरकार के

महाविद्यालयों एवं विषयों के संचालन के संबंध में गठित सोडाणी समिति की सिफारिशें अब तक न तो सार्वजनिक की गई हैं और न ही लागू की गई है। महासंघ ने यह भी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 के माध्यम से- नियम-2023 में परिवर्तन कर पाँच वर्षों के लिए 28500 रुपये के नियत वेतन पर सविदा टीचिंग एसोसिएट एवं अशैक्षणिक पदों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अभ्यर्चना भेजी जा चुकी है। महासंघ के अनुसार यह व्यवस्था अस्थायी, असुरक्षित एवं नीति-विरोधी है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के विपरित है।

आंगनवाड़ी कार्मिकों की समस्याओं की जानकारी देकर मानदेय बढ़ाने की मांग



निदेशक वासुदेव मालावत से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन

हेतु कार्मिकों को बेनस अथवा विशेष प्रोत्साहन राशि अवश्य दी जाए। ज्ञापन के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आग्रह किया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से केवल उसी विभाग से संबंधित कार्य लिया जाए, जिससे उन्हें मानदेय प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अतिरिक्त कार्यभार

के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग की मूल सेवाएं प्रभावित होती हैं। प्रतिनिधियों ने महिला पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) भर्ती शीघ्र निकालने तथा लंबे समय से कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अनुभव के आधार पर सुपरवाइजर पद पर समायोजित करने की भी मांग उठाई। आगामी बजट को ध्यान में रखते हुए संघ ने कार्मिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा हेतु पेंशन

सार-समाचार

स्वच्छता को लेकर विद्यार्थियों ने निकाली जागरूकता रैली

दौसा। राजस्थान नगरीय आधारभूत परियोजना (आरयूआईडीपी) की ओर से बुधवार को एफएसटीपी के बारे में नागरिकों को जागरूक करने और सुरक्षित स्वच्छता के महत्व को समझाने के लिए आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। विद्यार्थियों ने रैली के माध्यम से खुले में मल विसर्जन और अनियोजित मल अपशिष्ट निपटान से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया। विद्यार्थियों ने एफएसटीपी के माध्यम से गंदे पानी के सही उपचार के संदेश वाले पोस्टर और बैनर प्रदर्शित किए। नागरिकों को बताया गया कि कैसे घरों में सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए केवल अधिकृत डी स्ट्रेजिंग टैंकरों का उपयोग किया जाना चाहिए। इस अवसर पर आरयूआईडीपी के सहायक सामाजिक विकास अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा ने कहा कि एक स्वस्थ शहर के लिए सुरक्षित मल प्रबंधन आवश्यक है और एफएसटीपी तकनीक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि आपके घर का सेप्टिक टैंक खाली करवाना है तो टोल फ्री नंबर 1800 3137 342 पर फोन कर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको नगर परिषद की सफाई शाखा में 800 रुपये की रसीद कटवानी होगी। रैली के सफल आयोजन करवाने में उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के प्रधानाचार्य गिरिराज प्रसाद गुर्जर का सहयोग रहा।

जौला में रात्रि चौपाल के दौरान जन समस्याओं का हुआ निस्तारण

टोंक। जिला कलेक्टर कल्याण अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को तहसील पीपल् की ग्राम पंचायत जौला में रात्रि चौपाल आयोजित हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर ने परिवर्धियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर के समक्ष ग्रामीणों ने गांव में बंदरों द्वारा लोगों को काटने एवं सुअरों से फसलों को नुकसान होने से बचाने के लिए इन्हें पकड़कर दूर छुड़वाने का प्रार्थना पत्र दिया। जिला कलेक्टर ने सहायक विकास अधिकारी को समस्या का निदान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पेंशन सत्यापन की पेंडेंसी ज्यादा होने पर गंभीरता से लिया और इस कार्य को शत प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। स्कूल के स्टाफ ने विद्यालय में 5 कक्षा कक्षाओं के निर्माण कराने का प्रार्थना पत्र दिया। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को पीएम सूर्य घर योजना का अधिकाधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को योजना का बेहतर ढंग से प्रचार-प्रसार करने एवं लोगों को इस योजना का लाभ बताने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार को निर्देशित किया कि पटवारी गिरदावरी का कार्यकायत्कार के मोबाईल से ही करें, ताकि वह इस कार्य को भलीभांति सीख सकें। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया कि चौपाल में उनके आगे से पूर्व ही ग्रामीणों को विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया जायें। साथ ही ग्राम पंचायत की विद्युत, पेयजल संबंधी समस्याओं का पूर्व में ही निदान कर दिया जायें।

विमुक्त घुमन्तु एवं अद्धर्घुमन्तु समुदाय सहायता शिविर 15 फरवरी तक लगेगे

दौसा। विमुक्त घुमन्तु एवं अद्धर्घुमन्तु समुदाय के पात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए सहायता शिविरों में पूर्णता लाने के लिए शिविरों की अवधि 15 फरवरी तक की गई है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विमुक्त घुमन्तु एवं अद्धर्घुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों को केन्द्र, राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शिविरों के आयोजन 13 जनवरी से 31 जनवरी तक शिविर आयोजित किये गए थे। सहायता शिविरों में पूर्णता लाने के लिए शिविरों की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। सहायता शिविरों के माध्यम से विमुक्त घुमन्तु समुदाय के पात्र व्यक्तियों के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों हेतु आवेदन किये जाएंगे।

विराटनगर में एसडीओ का औचक निरीक्षण

पावटा।विराटनगर उपखण्ड अधिकारी विराटनगर कपिल कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को उपखण्ड क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम पंचायत भवन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुहाड़ा, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पापड़ा तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे ग्राम पंचायत भवन कुहाड़ा बंद मिला। वहीं कार्यालय परिसर में साफ-सफाई का अभाव तथा सड़क पर गंदा पानी जमा पाया गया। इस पर उपखण्ड अधिकारी ने नाराजगी जताते हुए पंचायत समिति विराटनगर के अधिकारियों को ग्राम पंचायत भवन बंद मिलने और साफ-सफाई नहीं होने के मामले में संबंधित कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी ने विद्यालयों का भी निरीक्षण कर बच्चों से बातचीत की और उनकी पढ़ाई एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुहाड़ा परिसर में भी साफ-सफाई का अभाव पाया गया। इस पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विराटनगर को आवश्यक सुधाराल्पक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपखण्ड अधिकारी ने अधिकारियों को सरकारी संस्थानों में नियमित उपस्थिति, स्वच्छता व्यवस्था और आमजन को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सांभर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव के लिए आंदोलन करने की मजबूरी

सांभरझील , (निसं)। सांभर झील रेलवे स्टेशन पर जरूरी ट्रेनों के ठहराव के लिए करीब दो दशक से उठ रही मांग को आज तक दफिनार किया जाता रहा है। तत्कालीन व वर्तमान सांसदों व विधायकों की अनदेखी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उनकी ओर से कोई ठोस प्रयास ही नहीं किए गए। दैनिक रेल यात्री संघ व सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं ने भी अपनी आवाज को कुछ हद तक बुलंद तो किया लेकिन परिणाम शून्य ही रहा। सांसद की अनदेखी व ठोस प्रयासों के अभाव के कारण सांभर रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मांग का सपना साल से अधूरा ही पड़ा है। भाजपा के अनेक कर्मठ कार्यकर्ताओं, अनेक पदाधिकारियों ने भी सांसद, रेल मंत्री, रेल प्रशासन को वाजिब मांग के आधार पर बाड़मेर-मथुरा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 20489/20490, बाड़मेर-देहली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 20487/20488, जयपुर – जोधपुर हाईकोर्ट एक्सप्रेस को सैकड़ों अप डाउन करने वाले लोगों व क्षेत्र की जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सांभर रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों का ठहराव कराए जाने के लिए अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन इन ट्रेनों का ठहराव तो दूर सांसद व रेल मंत्री की ओर से कोई आश्वासन आज तक नहीं मिला, यदि मिला तो आश्वासन पूरा नहीं हुआ।

हजरत दिलावर शाह बाबा का 2 दिवसीय वार्षिक उर्स शुरु

मनोहरपुर (निसं)। चौमू के रावण गेट व जामा मस्जिद के पास में स्थित हिन्नु मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत दिलावर शाह बाबा रहमतुल्लाह आलेह का 2 दिवसीय वार्षिक उर्स चिराग रोशन के साथ मे हुआ जो कि 5 फरवरी गुरुवार को कूल की रस्म के साथ मे विधिवत सम्पन्न होगा शहजाद खान लोहानी व रित्याज खान लोहानी ने बताया कि 4 फरवरी बुद्धवार को सुबह चिराग रोशन कर झंडा फहराया गया इसी के साथ मे रंग बिरंगे परिधानों में सज संवर कर यात्रीरों का आना शुरु होगया शाम को जामा मस्जिद मोहल्ले से गाजे बाजे के साथ मे चदर का जुलूस निकाला गया शाम 6 बजे बाद दरगाह के खादिमी के द्वारा बाबा के चदर पेश की गई।

व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण सम्पन्न

दौसा। आरकेसीएल एवं उन्नयन समिति के तत्वावधान में आयोजित व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन बुधवार को हुआ, एक महिने तक आयोजित प्रशिक्षण शिविर में 38 बालिकाओं को ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया गया।

जोधपुर-पाली-मारवाड़ कंकाणी को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित करेंगे- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत परियोजनाओं को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे

जयपुर, 4 फरवरी। जैसे-जैसे देश डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए बड़ी आवश्यकता के रूप में उभरी है। इसको और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बड़ी पहल की है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी प्रदेश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग तथा संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाएगी। इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार जोधपुर-पाली-मारवाड़ और कंकाणी सहित अन्य उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोरस घोषित करेगी। इन क्षेत्रों में निवेशकों के लिए फास्ट-ट्रैक लैण्ड अलॉटमेंट, यूटिलिटी कॉन्डिनेशन और सिंगल विण्डो रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत इंडिया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सेमीकंडक्टर मिशन के तहत परियोजनाओं को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान दिए जाएंगे। यह नीति सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगी और उच्च तकनीक आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित

भी करेगी। प्रदेश में निवेशकों को सेमीकंडक्टर यूनिट्स की स्थापना के लिए राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्विति

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्विति के लिए स्टेट लेवल सैंवशनिंग कमेटी तथा स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, नोडल विभाग होंगे।**

के लिए दो समितियों-स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी (एसएलएफसी) और स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

भूमिगत “चिकन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इस पट्टी की संवेदनशीलता को रेखांकित किया था। उनका कहना था कि इस हिस्से में किसी भी प्रकार का व्यवधान सैन्य आपूर्ति लाइनों को काट सकता है और सैनिकों की आवाजाही में बाधा डाल सकता है, साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को भी अलग-थलग कर सकता है। एनएफआर अधिकारियों के अनुसार, भूमिगत रेल ट्रैक अपात स्थितियों में भी निर्बाध सैन्य आवागमन सुनिश्चित करेगा। हाल के महीनों में बांग्लादेश का चीन की ओर झुकाव साफ तौर पर दिखाई दिया है। हाल ही में बांग्लादेश वायुसेना ने चीन के साथ ड्रोन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है।

शरद पवार ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अजित पवार ने एनसीपी(एसपी) के साथ विलय की कोई पहल नहीं की थी। शरद पवार ने कहा कि फडणवीस एनसीपी के दोनों गुटों के बीच हुई विलय संबंधी चर्चाओं का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्हें इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

लोकसभाध्यक्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दिलचस्प बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं कि ऐसी कोई किताब मौजूद नहीं है, जबकि राहुल गांधी ने किताब की प्रति दिखा दी है। क्या यह वरिष्ठ मंत्रियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है? स्थिति अब काफी कटु और खराब हो गई है और सत्तारूढ़ दल और राहुल गांधी के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस सत्र को सामान्य बनाना मुश्किल लग रहा है।

बोत्सवाना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) की सफल बसाहट के बाद अब असम का जंगली भैंसा भी मध्यप्रदेश के जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता नजर आएगा।

संसद में भारी हंगामा, प्रमंत्री भाषण नहीं दे सके

नई दिल्ली, 04 फरवरी। सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज होने वाला भाषण भी टल गया है। प्रधानमंत्री मोदी को आज शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था। इससे पहले सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा को गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सदन की कार्यवाही 12 बजे, फिर 2 बजे, और इसके बाद शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) एक गद्दार जा रहा है। इसका चेहरा देखो।” इसके बाद उन्होंने बिट्टू से हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए कहा, ”हैलो भाई, मेरे गद्दार दोस्त। चिंता मत करो, तुम वापस (कांग्रेस में) आ जाओगे।” मंत्री ने गांधी से हाथ मिलाने से इनकार करते हुए कहा, “देश के दुश्मन।” यह बातचीत उनके उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने (बिट्टू) प्रदर्शनकारी सांसदों के बारे में कहा था कि “वे ऐसे बैठे हैं जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो।”

प.बंगाल चुनावों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) राज्य के दौरो के बाद सांसदों के साथ की जा रही ये वन-टू-वन बैठकें पार्टी की चुनावी रणनीति को और धार देने के लिए बेहद अहम मानी जा रही हैं। चुनावों से पहले इस बैठक को

सुप्रीम कोर्ट ने नीट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उठाए गए हैं, जिसके माध्यम से स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश के लिए कट-ऑफ परसेंटाइल को उस स्तर तक कम कर दिया गया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने असामान्य रूप से बहुत कम बताया है। इसमें कट-अफ

ममता बनर्जी ने सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) इसका चुनाव पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। बनर्जी और उनकी पार्टी ने बंगाल में फर्जी मतदान करने की कला में महारत हासिल कर ली थी और उन्होंने मतदाता सूचियों की खामियों का फायदा उठाकर कई सीटों पर जीत हासिल की थी। टीएमसी को मतदाता सूचियों में मौजूद फर्जी नामों की पूरी जानकारी रहती थी और वह नियमित रूप से अपने समर्थकों को फर्जी मतदान के लिए भेजती थी। कम से कम 56 लाख नाम ऐसे पहचाने गए हैं जो फर्जी थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे नाम भी हटाए गए, जिनके नाम पर दर्ज लोग बहुत पहले मर चुके थे। इसके साथ-साथ बांग्लादेश से सीमा पार कर आए अवैध प्रवासी भी बंगाल के चुनावों में नियमित रूप से मतदान करते रहे थे। इन सभी समूहों को मिलाकर देखा जाए तो मतदाता सूची का सही और ईमानदार संशोधन बड़ी संख्या में फर्जी और अवैध मतदाताओं को हटाने का कारण बन सकता है, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। ममता बनर्जी को ऐसे

चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बैच ने निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि एसआईआर के तहत नोटिस सावधानी से भेजे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “ईसीआई को, कृपया नोटिस सावधानी से भेजें। आप प्रतिष्ठित लेखकों आदि को नोटिस नहीं भेज सकते।” ये टिप्पणियाँ उस घटना के कुछ हफ्तों बाद आई हैं, जब चुनाव आयोग ने पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश (सेवानिवृत्त), नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी सहित कई सार्वजनिक हस्तियों को एसआईआर के तहत नोटिस भेजे थे। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ महिलाओं के नाम केवल इसलिए हटा दिए गए क्योंकि उन्होंने शादी के बाद अपना सरनेम बदल लिया। उन्होंने कहा, “मान लीजिए बेटी शादी के बाद ससुराल चली जाती है, वह पति का सरनेम इस्तेमाल कर रही है, इसे भी मिसमैच माना गया, कुछ बेटियां ससुराल चली गईं, उनके नाम भी हटा दिए गए।”

■ पर, यह महसूस करते हुए कि अगर, संशोधित वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई तो तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में “ड्रामा” करने का निर्णय लिया। अगर, सुप्रीम कोर्ट इस “ड्रामे” से प्रभावित होकर, एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित कर देता है तो प्रजातंत्र के लिए काला दिन होगा।

फर्जी वोटों से फायदा मिलता रहा है और अब उन्हें इसमें समस्या दिखाई दे रही है। इसलिए वह इस प्रक्रिया को बदनाम करने और खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। दुर्भाग्य से, सर्वोच्च न्यायालय इस चुनौती का सामना नहीं कर पाया और ऐसा लगता है कि वह उनके राजनीतिक दबाव के आगे झुक गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के राजनीतिक दांव का सामना नहीं कर पाता और मतदाता सूची का सही संशोधन खतरे में पड़ जाता है, तो यह लोकतंत्र और मतदान के लिए दुखद दिन होगा। अदालत में उनके राजनीतिक भाषण को रोकने के बजाय, जज उनके दबाव वाले तरीके के सामने झुक गए और उन्हें लगभग पंद्रह मिनट तक बोलने दिया। अदालत ने मुख्य चुनाव

युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मु.मंत्री पद की शपथ ली

इंफाल, 04 फरवरी। हिंसाग्रस्त मणिपुर को लंबे राष्ट्रपति शासन के बाद अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मार्शल आर्ट के धुरंधर मैतेई समुदाय के युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ली। इससे पहले आज उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया।

वहीं, भाजपा विधायक नेमचा किपगेन ने मणिपुर के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। किपगेन कुकी समुदाय से हैं। इसके अलावा, नागा पीपुल्स फ्रंट के विधायक एल डिखो ने भी उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। भाजपा के गोविंददास कोथीजम और एनपीपी के के लोकेन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। नेमचा किपगेन ने नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से डिजिटल माध्यम से शपथ ली। विधायक दल की मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें खेमचंद (62 वर्षीय) को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में भाजपा विधायक दल

आयुक्त को निर्देश दिया कि वह उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों, जैसे विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया में अपनाई जा रही पद्धतियों, पर ध्यान दें। अदालत तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर आगे सुनवाई करेगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया में नामों में छोटे-मोटे अंतर के आधार पर लोगों के नाम मतदाता सूची से मनमाने तरीके से हटाए जा रहे हैं। बनर्जी ने नाम और उपनाम लिखने के अलग-अलग तरीकों की ओर ध्यान दिलाया, जो वर्तमान व्यवस्था का हिस्सा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे किसी भी अंतर के कारण मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं।

■ **कुकी समुदाय के भाजपा विधायक नेमचा किपगेन को उपमुख्यमंत्री बनाया गया**

की डेढ़ घंटे बैठक चली, जिसमें खेमचंद के नाम पर सहमति बनी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी, पर्यवेक्षक तरुण चुच की उपस्थिति में भाजपा मुख्यालय में विस्तार से हुई विधायक दल की बैठक में कई नामों पर विचार हुआ था। चर्चा थी कि कुकी ब्रनाम मैतेई समुदाय के बीच संतुलन साधने के लिए नई सरकार में कुकी समुदाय को उपमुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। हालांकि, मुख्यमंत्री के मामले में लिए गए निर्णय से साफ था कि पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की पसंद को तबज्जो नहीं मिली। बीरेन सात बार के विधायक मैतेई समुदाय के ही गोविंद दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे।



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री



राजस्थान में आयोजित
भारत की सबसे बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय



13th
STONE MART 2026
Stone for Sustainability
5 - 8 February, 2026
JECC, SITAPURA, JAIPUR, RAJASTHAN, INDIA



JAIPUR
ARCHITECTURE
FESTIVAL
6th-7th February 2026
JECC, SITAPURA, JAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

5 फरवरी, 2026 | प्रातः 9:30 बजे
मुग्धा कन्वेंशन हॉल, जेईसीसी, सीतापुरा, जयपुर

इंडिया स्टोनमार्ट 2026 में पहली बार

26+ अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में इंडिया स्टोनमार्ट की वेबसाइट

स्टोनमार्ट का स्मार्ट डिजिटल मोबाइल ऐप

अब तक का सबसे विशाल प्रदर्शनी क्षेत्र

विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएँ

पत्थर उद्योग और आध्यात्मिक संस्थानों के बीच सहयोग

‘एक जिला - एक उत्पाद’ (ODOP) पवेलियन

एमएसएमई (MSME) केन्द्रित प्रमोशन और स्टॉल इंटीग्रेशन

आप सादर आमंत्रित हैं

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

 www.stonemart-india.in

 info@stonemart-india.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान









राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शांतिपिंग सेंटर, टॉक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdutr@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुम्भाना हाउस, हनुमान हल्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-चूधरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908